चैत्र कृष्ण - 12 ■ संवत 2081 ■ वर्ष - 20 ■ अंक - 238 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- बेंगलूरु » बुधवार » 26-03-2025 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

4 मानवीय मूल्यों के साथ प्रौद्योगिकी विकास के लिए आगे बढें युवा : बागडे

6 संघ के 'कर्नाटक मंथन' में नए संकल्प, नई दिशाएं

7 कॉमेडी के नाम पर किसी को भी अपमानित करना गलत है : कंगना रनौत

फर्स्ट टेक

कन्नड़ 'बिग बॉस' के दो पूर्व प्रतिभागियों को गिरफ्तार किया गया

बेंगलूरु/भाषा। कन्नड़ 'बिग बॉस' के दो पूर्व प्रतिभागियों को सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो क्लिप में कथित तौर पर हथियार लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रजत किशन और विनय गौड़ा को आज पुलिस हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों को कथित तौर पर 18 सेकंड के वीडियो क्लिप में सार्वजनिक स्थान पर एक चाकू पकड़े हुए देखा गया था, जिसे उनमें से एक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया गया था। यह क्लिप जल्द ही वायरल हो गई, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। वीडियो में दिख रहा चाकू अभी बरामद नहीं हुआ है।

नागपुर हिंसा के मामले में अब तक 114 लोग गिरफ्तारः पुलिस आयुक्त

नागपुर/भाषा। नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के सिलसिले में 114 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह बात कही। नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंदर सिंघल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पुलिस हिंसा के समय प्रसारित की गई सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है और उन्हें अपलोड करने में शामिल कुछ लोगों की पहचान की गई है। अधिकारियों के अनुसार, छत्रपति संभाजीनगर में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विहिप के विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र पुस्तक की पंक्तियां लिखी'चादर' जलाए जाने की निराधार अफवाह फैलने पर 17 मार्च को नागपुर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी हुई।

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना आज से बंद, अल्पावधि जमा जारी रहेगी

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बेहतर होती बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वर्ण मौद्रीकरण योजना (जीएमएस) को बुधवार से बंद करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि बैंक एक से तीन साल वाली अपनी अल्पकालिक स्वर्ण जमा योजनाओं को जारी रख सकते हैं। सरकार स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के तहत नवंबर, 2024 तक लगभग 31,164 किलोग्राम सोना जुटा चुकी थी। सरकार ने इस योजना की घोषणा 15 सितंबर, 2015 को की थी। इसे लाने का उद्देश्य लंबी अवधि में सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के साथ देश में परिवारों और संस्थानों द्वारा रखे गए सोने को जुटाना था।

आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय एवं वैश्विक ताकत बनकर उभरा भारत : अमित शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। आपदा प्रबंधन में आर्थिक सहायता देने में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में दावा किया कि पिछले दस साल में भारत आपदा प्रबंधन के मामले में रानीय ही नहीं क्षेत्रीय एवं वैश्विक ताकत बनकर उभरा है तथा इसे दुनिया भी यह स्वीकार कर रही है।

उच्च सदन में शाह ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसमें सत्ता के केंद्रीयकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के बारे में इस विधेयक में न केवल प्रतिक्रियात्मक रवैया अपनाने बल्कि पहले से तैयारी करने, अभिनव प्रयासों वाले और सभी की भागीदारी वाले रवैये को अपनाने पर जोर दिया गया है।

गृह मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने सरकारी संशोधनों के साथ इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सदन ने विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा के जोखिमों को घटाने के लिए विश्व के समक्ष जो 10 सूत्री एजेंडा रखा है, उसे 40 देशों ने अपना लिया है और उसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधयक में न केवल राज्य सरकारों बल्कि आम लोगों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। शाह ने कहा, पिछले दस सालों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, हम रानीय स्तर के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक ताकत बनकर उभरे हैं, यह पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारत की सफलता गाथा को लंबे समय तक बनाये रखने के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह सफलता गाथा सरकार की नहीं, बल्कि पूरे देश की है।

शाह ने कहा कि आपदा प्रबंधन की लड़ाई संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाने के साथ-साथ जवाबदेह बनाये बिना नहीं लड़ी जा सकती है। उन्होंने कहा कि विधेयक में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि आपदा का सीधा रिश्ता जलवायु परिवर्तन से है। उन्होंने कहा कि आपदा रोकने के लिए आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन पर नजर रखी जाए और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। उन्होंने वेदों का जिक्र किया और कहा कि इसमें न केवल पृथ्वी बल्कि अंतरिक्ष तक को बचाने की बात कही गयी है। गृह मंत्री ने सृष्टि को बचाने के लिए भारत द्वारा प्राचीन समय से किए जा रहे उपायों का जिक्र करते हुए हड़प्पा सभ्यता का भी उल्लेख किया।

मोदी सरकार ने अलगाववाद को जम्मू-कश्मीर से बाहर निकाल दिया : शाह

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि 'हुर्रियत कॉन्फ्रेंस' से जुड़े दो संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। शाह ने कहा कि यह कदम भारत की एकता को मजबूत करेगा। उन्होंने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की एकीकरण नीतियों ने जम्मू-कश्मीर से अलगाववाद को बाहर कर दिया है। शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''हुर्रियत से जुड़े दो संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। मैं भारत की एकता को मजबूत करने की दिशा में अहम इस कदम का स्वागत करता हूं और ऐसे सभी समूहों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं तथा अलगाववाद को हमेशा के लिए खत्म कर दें।''

उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत भारत के निर्माण के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ी जीत है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर का एक अलगाववादी संगठन है। इसके अधिकतर घटकों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है।

राज्यसभा में सभापति ने विश्वास जताया

विश्व गुरू तो भारत ही होगा : धनखड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में मंगलवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने विश्वास जताया कि विश्व गुरु तो भारत ही होगा। शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कृत्रिम मेधा यानी आर्टीफीशियल इंटेलिजेन्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी आबादी एआई के कार्यबल का हिस्सा है फिर भी इस क्षेत्र में भारत को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी, वह नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विश्व गुरू वह होगा जिसके पास एआई की ताकत होगी इसलिए भारत को 'मेक इन इंडिया' के साथ साथ मेक 'एआई इन इंडिया' के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। इस पर सभापति धनखड़ ने मुस्कुराते हुए कहा ''विश्व गुरु तो भारत ही होगा।''

राघव चड्ढा ने कहा कि आज का दौर एआई की क्रांति का युग है और अमेरिका के पास अपने चैटजीपीटी, जेमिनी, एन्थ्रॉपिक ग्रॉक जैसे मॉडल हैं वहीं चीन ने डीपसीक जैसा सबसे ज्यादा क्षमता वाला तथा सबसे कम लागत से बना एआई मॉडल तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एवं चीन के पास अपने अपने स्वदेशी मॉडल हैं लेकिन भारत कहां है, उसका अपना जनरेटिव एआई मॉडल कहां है?

चड्ढा ने कहा कि वर्ष 2010 से 2022 तक दुनिया में जितने पेटेंट पंजीकृत हुए उनका 60 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका ने और 20 फीसदी हिस्सा चीन ने हासिल किया वहीं भारत ने मात्र आधा प्रतिशत ही हासिल किया। आप सदस्य ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन ने पिछले चार पांच साल में एआई पर खासी रिसर्च की और उसमें निवेश तथा प्रयोग किए। उन्होंने कहा कि कुल एआई कार्य बल का 15 फीसदी हिस्सा भारतीय हैं। भारत के पास प्रतिभा है, मेहनती लोग हैं, ब्रेन पॉवर है, डिजिटल अर्थव्यवस्था है, हमारे यहां 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपभोक्ता हैं। फिर भी वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर एआई के संदर्भ में नजर रहीं आता। वह एआई उत्पादक बनने के बजाय एआई उपभोक्ता बन गया है।

भाजपा नेता सी एन अश्वथ नारायण ने लगाया आरोप

कनार्टक में स्मार्ट मीटर टेंडर प्रक्रिया में 15,568 करोड़ रुपए की हुई 'अनियमितता'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सी एन अश्वथ नारायण ने मंगलवार को आरोप लगाया कि 'बेंगलूरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड' (बीईएससीओएम) और अन्य इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनियों (ईएससीओएमएस) की स्मार्ट मीटर निविदा प्रक्रिया में लगभग 15,568 करोड़ रुपये की 'अनियमितता' हुई है।

अधिकारियों के अनुसार, स्मार्ट मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो बिजली की खपत, वोल्टेज स्तर, लोड और विभिन्न अन्य तकनीकी मापदंडों जैसे डेटा को रिकॉर्ड करता है। यह जानकारी समय-समय पर सर्वर को प्रेषित की जाती है। निविदा प्रक्रिया में सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर 'पक्षपात और अनियमितता' करने का आरोप लगाते हुए विधायक ने दावा किया कि इस गड़बड़ी का पैमाना और भी बड़ा है और इस बात पर जोर दिया कि ईएससीओएमएस को कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) के नियमों का पालन करना चाहिए।

पूर्व उपमुख्यमंत्री का बयान ऊर्जा विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने में अनियमितता के आरोपों को खारिज करने के एक दिन बाद आया है। बीईएससीओएम के एमडी शिवशंकर ने जोर देकर कहा कि स्मार्ट मीटर का खरीद मूल्य वैज्ञानिक रूप से निर्धारित किया गया था और पूरी पारदर्शिता के साथ इस पर अमल किया गया।

संवाददाता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने तर्क दिया कि कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी) के नियम स्मार्ट मीटर के उपयोग को अनिवार्य नहीं बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अस्थायी कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी और नए ग्राहकों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नियमों का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर तभी अनिवार्य किए जा सकते हैं, जब सभी मौजूदा मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदल दिया गया हो।

नारायण ने कहा, ''केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियमों के तहत भी स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं हैं। कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम के तहत बोली क्षमता का उल्लेख निविदा में नहीं किया गया था। यह 6,800 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी।''

भाजपा विधायक ने बताया कि केटीपीपी अधिनियम के तहत, आवश्यक कारोबार 1,920 करोड़ रुपये होना चाहिए, जबकि निविदा का संशोधित अनुबंध मूल्य 107 करोड़ रुपये वार्षिक निर्दिष्ट किया गया था।

भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उसने अगले पांच वर्षों में दूध उत्पादन वर्तमान 23.9 लाख मीट्रिक टन से 30 लाख मीट्रिक करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल में यह भी कहा कि जब से मोदी सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) शुरू किया है, तब से देश में दूध उत्पादन में 63.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सरकार को अगले तीन वर्षों में इसमें 15 प्रतिशत की और वृद्धि होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ''भारत अब दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमने अगले पांच वर्षों में वर्तमान 23.9 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन से 30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।'' सिंह ने कहा कि देश में करीब 10 करोड़ लोग दूध उत्पादन में लगे हुए हैं, जिनमें से 75 प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 471 ग्राम है।

न्यायमूर्ति वर्मा पर लगे आरोपों की आंतरिक समिति ने जांच शुरू की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/एजेन्सी। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने मंगलवार को जांच शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि तीनों न्यायाधीश दोपहर करीब एक बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के 30, तुगलक क्रीसेंट स्थित आधिकारिक आवास पर पहुंचे। उन्होंने करीब 45 मिनट तक न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के अंदर रहे और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। समिति के सदस्यों में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया कि उन सदस्यों ने उस कमरे की जांच की, जहां आग लगने के बाद कथित तौर पर नकदी मिला था।

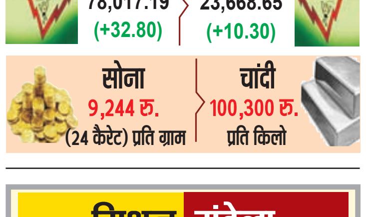

यह आरोप निराधार है कि जीएसटी प्रगतिशील नहीं है : वित्त मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विपक्ष के कई सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह बात पूरी तरह निराधार है कि जीएसटी प्रगतिशील नहीं है। उन्होंने वित्त विधेयक, 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि कॉरपोरेट कर में कटौती से निवेश में बढ़ोतरी हुई है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से वित्त विधेयक को मंजूरी दी।

सीतारमण ने कहा, ''यह सच नहीं है कि कॉरपोरेट कर में कटौती से बड़े कारोबारी समूहों को फायदा हो रहा है।'' उन्होंने कहा कि इससे कई कारोबारी इकाइयों का फायदा हुआ है और निवेश बढ़ाने में भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि यह आरोप निराधार है कि जीएसटी प्रगतिशील नहीं है।

वित्त मंत्री ने कहा, ''सबसे अमीर 20 प्रतिशत नागरिक परिवार के स्तर पर 41.4 प्रतिशत जीएसटी का योगदान देते हैं जो कुल जीएसटी का 14.2 फीसदी है, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत लोग 28 प्रतिशत जीएसटी का योगदान देते हैं जो कुल जीएसटी का 9.6 फीसदी है। इसलिए यह दलील गलत है कि जीएसटी प्रगतिशील नहीं है।'' उनके मुताबिक, सबसे गरीब 50 फीसदी लोगों को 7.3 फीसदी औसत प्रभावी दर का सामना करना पड़ता है, जबकि जीएसटी से पहले की व्यवस्था में ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है और वित्त मंत्रियों का समूह जीएसटी की दरों पर फैसला करता है।

अय्यर की आक्रामक पारी से पंजाब किंग्स ने गुजराज टाइटंस को हराया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। कप्तान श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स के लिए अपने पहले मैच में 42 गेंदों पर नाबाद 97 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम ने मंगलवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग मैच में गुजरात टाइटंस पर 11 रन की जीत दिलायी।

श्रेयस ने अपनी आतिशी पारी में नौ छक्के और पांच चौके लगाए लेकिन वह आईपीएल में अपना पहला शतक पूरा नहीं कर सके क्योंकि आखिरी ओवर में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला।

मोहम्मद सिराज के इस ओवर से शशांक सिंह (16 गेंदों पर 44 रन) ने 23 रन बटोरकर पंजाब की पारी को शानदार तरीके से समाप्त किया।

शशांक ने अपनी शानदार पारी के दौरान छह चौके और दो छक्के लगाए। पंजाब किंग्स ने पांच विकेट पर 243 रन बनाने के बाद गुजरात टाइटंस को पांच विकेट पर 232 रन पर रोका कर अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया।

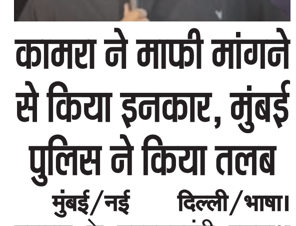

कामरा ने माफी मांगने से किया इनकार, मुंबई पुलिस ने किया तलब

मुंबई/नई दिल्ली/भाषा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए कथित रूप से आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल को लेकर अपने रुख पर अड़िग हास्य कलाकार कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। वहीं शिंदे ने कामरा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मर्यादा व सीमा बनाए रखने की हिदायत दी और जोर देकर कहा कि वह तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करते। कामरा ने मुंबई में कार्यक्रम के दौरान विवादास्पद टिप्पणी से मचे घमासान के बाद सोमवार देर रात को एक पोस्ट में कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा... मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इसके शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। वहीं शिंदे ने कामरा द्वारा उनके बारे में की गई टिप्पणी की तुलना 'सुपारी लेकर किसी के खिलाफ बोलने' से करते हुए कहा कि कटाक्ष करते समय मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, अन्यथा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मुंबई पुलिस ने कामरा को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि 36 वर्षीय कामरा को मानहानि के एक मामले में मुंबई में खार थाने में पेश होने को कहा गया है।

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

शर्मिंदा सदन

अंटशंट जो बोल रहा कुछ,
नेता वो बकवादी है।
आरोपित करता दूजे को,
ज्यों वादी प्रतिवादी है।
हमने ऐसों को चुन करके,
करी वोट बरबादी है।
शर्मिंदा जो करे सदन को,
ये कैसी आजादी है?

इस वर्ष गर्मियों में दस प्रतिशत अधिक बिजली मांग के लिए तैयार रहें

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। देश में इस साल अधिक गर्मी पड़ने के मौसमी अनुमानों को देखते हुए विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि भारत को इस गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग में नौ से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पिछले साल अखिल भारतीय स्तर पर बिजली की अधिकतम मांग 30 मई को 250 गीगावाट को पार कर गई थी जो अनुमान से 6.3 प्रतिशत अधिक थी। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित गर्मी का तनाव बिजली की मांग को बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों में से एक है।

वर्तमान में उद्योग, घरेलू उपभोग और कृषि क्षेत्र की कुल बिजली खपत में क्रमशः 33 प्रतिशत, 28 प्रतिशत और 19 प्रतिशत हिस्सेदारी है। दिल्ली स्थित शोध संस्थान 'काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर' में वरिष्ठ कार्यक्रम प्रमुख दिशा अग्रवाल के मुताबिक, पिछले एक दशक में घरेलू बिजली की मांग सबसे तेजी से बढ़ी है।

घरेलू बिजली की खपत का हिस्सा 2012-13 में 22 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 25 प्रतिशत हो गया। यह तेजी आर्थिक वृद्धि और बढ़ते तापमान के कारण घरों एवं दफ्तरों को ठंडा रखने की बढ़ती जरूरतों के कारण है। अग्रवाल ने कहा कि 2024 की गर्मियों में रिकॉर्डतोड़ तापमान के बीच कमरे के एयर कंडीशनर की बिक्री में सालाना आधार पर 40-50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। उन्होंने कहा, ''भारत को अब लंबी गर्मी और 9-10 प्रतिशत की बिजली की मांग में वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि, हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि यह चरम मांग केवल थोड़े समय तक ही रहेगी।'' अग्रवाल ने कहा कि भारत की बिजली की खपत 2020-21 से सालाना लगभग नौ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि इससे पहले के दशक में यह पांच प्रतिशत प्रति वर्ष थी।

दिल्ली का एक लाख करोड़ रुपए का बजट पेश

महिला सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचा विकास पर जोर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट मंगलवार को पेश किया। इसमें यमुना की सफाई, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचा विकास, जल तथा सपर्क सहित 10 क्षेत्रों पर जोर देते हुए राष्ट्रीय राजधानी को आत्मनिर्भर बनाने का खाका पेश किया गया है।

वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाल रही गुप्ता ने अपने 138 मिनट के बजट भाषण में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार के पहले बजट को ''ऐतिहासिक'' करार दते हुए कहा कि ''भ्रष्टाचार और अक्षमता'' का दौर अब समाप्त हो गया है। भाजपा नीत सरकार ने दिल्ली में 26 वर्ष के बाद बजट प्रस्तुत किया है। पार्टी ने पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) को हराकर सत्ता में वापसी की थी। शहर में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 28,000 करोड़ रुपये कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट परिव्यय पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 31.5 प्रतिशत अधिक है।

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए भाजपा सरकार ने 300 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। शहर में 10 वर्ष से अधिक समय तक सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी (आप) पर कटाक्ष करते हुए गुप्ता ने प्रसिद्ध कवि बशीर बद्र की पंक्तियां दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने ''लूटा है'' दोहराईं। गुप्ता ने कहा कि बजट राष्ट्रीय राजधानी के विकास की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने कहा, ''पिछले एक दशक में दिल्ली विकास के हर पहलू में पिछड़ गई। पिछली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की आर्थिक सेहत को दीमक की तरह बर्बाद कर दिया।'' बजट में मुख्य तौर पर यमुना नदी की सफाई और पुनरुद्धार पर विशेष जोर दिया गया है, जो ''साबरमती रिवर फ्रंट' परियोजना से प्रेरित है।

सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया जिससे यह सुनिश्चित होगा कि '40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट' (एसटीपी) के विकेंद्रीकरण के माध्यम से केवल उपचारित पानी ही नदी में जाए। इसके अलावा एसटीपी की मरम्मत तथा उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये और पुरानी सीवर लाइन को बदलने के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया तथा संबंधित परियोजनाओं के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,874 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र स्थापित करने और 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' पहल का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में 400 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों की स्थापना के लिए 320 करोड़ रुपये के आवंटन प्रस्ताव भी शामिल है।

दिल्ली सरकार ने गर्भवती महिलाओं को 'पोषक तत्व किट' और 21,000 रुपये का भत्ता प्रदान करने के लिए 210 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री ने 10 से 13 नए अस्पताल के निर्माण में तेजी लाने की योजना की भी घोषणा की, जिसके लिए विशेष रूप से 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर बेहतर परिवहन संपर्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। परिवहन क्षेत्र के लिए कुल 12,952 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार गुलाबी टिकट के स्थान पर 'कार्ड' जारी करेगी। महिलाओं के कल्याण के मकसद से पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

गुप्ता ने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को निवेश व नवाचार के अनुकूल शहर बनाना है। इसके लिए नई औद्योगिक नीति और नई गोदाम नीति पेश की जाएगी। व्यापारी कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, दिल्ली में पहली बार वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह हर दो वर्ष में आयोजित होगा। लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए मधुमक्खी पालन सहित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। दिल्ली सरकार एक प्रमुख सांस्कृतिक पहल के तहत 30 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ अंतरराष्ट्रीय फिल्म 'महोत्सव' का आयोजन करेगी।

आप ने दिल्ली के बजट को हवा हवाई, 'आधारहीन एवं अवास्तविक' करार दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने मंगलवार को पेश बजट को ''हवा हवाई'' बताते हुए इसे ''आधारहीन और अवास्तविक'' करार दिया।

आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने से परहेज किया। उन्होंने कहा, अगर सरकार के पास वाकई एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व होता तो वह विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने में संकोच नहीं करती। उसने इसे इसलिए छिपाया, क्योंकि आंकड़े इस खोखले बजट के पीछे की सच्चाई को उजागर कर देते।

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भाजपा पर शिक्षा, स्वास्थ्य और नगरपालिका सेवाओं जैसे आवश्यक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन में कटौती करने का आरोप लगाया एवं कहा कि बजट से सार्वजनिक सेवाओं को कमजोर करने की 'सरकार की मंशा' का पता चलता है। उन्होंने कहा, दस साल में पहली बार शिक्षा बजट 20 प्रतिशत से नीचे चला गया है, जो सरकारी स्कूलों को नष्ट करने के उनके एजेंडे को दर्शाता है। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज सेवाओं को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य खर्च में भी कटौती करके इसे 13 प्रतिशत कर दिया गया है – जो एक दशक में सबसे कम है।

धारावी पुनर्विकास के लिए अब तक 63,000 इकाइयों का सर्वेक्षण पूरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी-बस्ती धारावी की पुनर्विकास परियोजना के तहत जारी सर्वेक्षण ने इसकी रिहायशी एवं वाणिज्यिक संरचनाओं का नक्शा बनाने और दस्तावेजीकरण के लिए 2007-08 में किए गए पिछले सर्वेक्षण के स्तर को पार कर लिया है। अधिकारियों ने कहा कि 63,000 से अधिक ठिकानों का पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका है और यह गिनती अब भी जारी है। झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के दिशानिर्देशों के तहत केवल भूतल के निवासियों को आमतौर पर मुफ्त आवास के लिए पात्र माना जाता है।

धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसवीआर श्रीनिवास ने कहा, हमारे सर्वेक्षण ने एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मील का पत्थर पार कर लिया है। यह पुनर्विकास योजना केवल भूतल के मकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऊपरी मंजिल की संरचनाओं को भी कवर करती है। यह दर्शाता है कि सरकार सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। धारावी में कोई भी पीछे नहीं रहेगा।

सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अबतक 95,000 से अधिक मकानों के लिए लेन मुआयना पूरा हो चुका है, जबकि 89,000 से अधिक मकानों को क्रमांकित किया गया है, और 63,000 से अधिक मकानों के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। वर्ष 2007-08 में हुए पिछले सर्वेक्षण के उलट इस सर्वेक्षण में भूतल और ऊपरी मंजिल की संरचनाएं, मौजूदा एसआरए भवन, आरएलडीए भूमि पर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग और सभी धार्मिक संरचनाएं भी शामिल हैं।

श्रीनिवास ने कहा, हम सर्वेक्षण के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। संख्याएं स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि धारावी के लोग पुनर्विकास के पक्ष में हैं और सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

परियोजना को पूरा करने के लिए गठित नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएमडीपीएल) लगभग 1.5 लाख आवास बनाने की तैयारी कर रही है क्योंकि अधिकांश झोपड़ियां जी+2 स्तर तक बढ़ गई हैं, जिससे पुनर्वास की जरूरत वाले आवासों की संख्या बढ़ गई है।

पानीपत की लड़ाई मराठों की हार का नहीं, बल्कि बहादुरी का प्रतीक : फडणवीस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों की हार का नहीं, बल्कि उनकी बहादुरी का प्रतीक है। अंतिम सप्ताह के 'प्रस्ताव' पर विपक्ष की ओर से शुरू की गई चर्चा का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के आगरा में 'शिव स्मारक' (छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक) का निर्माण कर रही है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के पानीपत में भी एक स्मारक बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जहां 1761 में मराठों और (अफगान शासक) अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इस पर विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (राकांपा-सपा) के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने पूछा कि पानीपत में स्मारक क्यों बनाया जा रहा है, जहां अब्दाली ने मराठों को हराया था। आव्हाड ने कहा, पानीपत हमारी वीरता का प्रतीक नहीं है। यह मुझे हार की याद दिलाएगा। यहां अहमद शाह अब्दाली और (मराठा सेनापति) सदाशिवराव भाऊ के बीच युद्ध हुआ था। दुनिया में पराजय के लिए कोई स्मारक नहीं है। इस पर फडणवीस ने कहा, ''पानीपत की लड़ाई मराठों की हार का नहीं, बल्कि बहादुरी का प्रतीक है।'' ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मराठों की वीरता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में बादशाह मराठों को 'चौथ' (एक तरह का कर) दे रहा था और जब अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो उसने (दिल्ली के बादशाह ने) मराठों को पत्र लिखकर दिल्ली को बचाने के लिए आने का आग्रह किया। फडणवीस ने कहा कि मराठा दिल्ली गए और अब्दाली को हराया, जिसके बाद अफगान शासक भाग गया तथा यमुना नदी के किनारे डेरा डाला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद अब्दाली ने मराठों को पत्र लिखकर युद्ध-विराम की पेशकश की और कहा कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को उसका क्षेत्र माना जाए, जबकि देश का बाकी हिस्सा मराठों का रहेगा। फडणवीस ने कहा, मराठों का इस (संघर्ष) से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अब्दाली को एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। मराठों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, ताकि तीनों क्षेत्र भारत का हिस्सा बने रहें।

सरकार ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 7.81 लाख सिमकार्ड, 83 हजार से अधिक व्हॉट्सऐप खाते ब्लॉक किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस साल 28 फरवरी तक डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े 7.81 लाख से ज्यादा सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने सदन को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा चिह्नित कुल 2,08,469 आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (आईएमईआई) हर फोन को दिया जाने वाला एक विशिष्ट नंबर होता है।

मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने डिजिटल अरेस्ट के लिए इस्तेमाल किए गए 3,962 से ज्यादा स्काइप आईडी और 83,668 व्हॉट्सऐप अकाउंट की पहचान करके उन्हें ब्लॉक कर दिया है। कुमार ने जवाब में कहा, वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए आई4सी के तहत नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली 2021 में शुरू की गई है। अब तक 13.36 लाख से अधिक शिकायतों में लगभग 4,386 करोड़ रुपये बचाए गए हैं।

संभल में मेले की अनुमति न दिए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

संभल/भाषा। संभल के शहवाजपुर सुरा नगला गांव में मंगलवार को लगने वाले मेले की प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने के बाद वहां एहतियात के तौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्रीश चंद्र ने पत्रकारों को बताया कि आज इस स्थान पर किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जा रहा है।

एएसपी ने कहा,यह आयोजन एक लुटेरा, आक्रांता और हत्यारे की याद में किया जाता रहा है। इसी कुरीति को सभी लोगों ने समझा और उसे त्याग दिया। उन्होंने कहा कि सभी जगह पूर्ण रूप से शांति है और पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है। चंद्र ने कहा, आज इस मजार (सैयद सालार मसूद गाजी की) पर कोई नहीं आ रहा है। इस तथ्य को सभी ने समझा है कि एक आक्रांता की याद में होने वाले वाले आयोजन में शामिल नहीं होना है। उन्होंने कहा कि लोग इस तथ्य को समझ कर (मजार पर) नहीं आ रहे हैं तथा पूर्णतः शांति है एवं जगह-जगह पुलिस तैनात है।

उन्होंने बताया, कही भी मेले का आयोजन नहीं होगा। किसी को भी सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है और जो भी अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। संभल के अधिकारियों ने आक्रमणकारी महमूद गजनवी के भांजे और सैयद सालार मसूद गाजी की याद में आयोजित होने वाले 'नेजा मेला' के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि लूटपाट के उद्देश्य से देश में आये किसी व्यक्ति की याद में आयोजन उचित नहीं है।

तीन दिवसीय नेजा मेला 25 मार्च से शुरू होना था। संभल में पिछले साल नवंबर को शहर के कोट गर्वी इलाके में शाही जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गयी थी। हिंसा में चार लोग मारे गए थे और सुरक्षाकर्मियों समेत कई अन्य घायल हो गए थे।

प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य जांच की मांग की

शेखपुरा (बिहार)/भाषा जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति पर मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार को समारोहों और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने से रोका जा रहा है, ताकि उनके बारे में सार्वजनिक रूप से किसी तरह की चर्चा ना हो। शेखपुरा जिले में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किशोर ने कहा कि इसके बावजूद जद(यू) प्रमुख अजीब व्यवहार के कारण खबरों में बने रहते हैं। किशोर ने कहा, मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता सबसे पहले उनके करीबी सहयोगी दिवंगत सुशील मोदी ने 2023 में जताई थी। पिछले कुछ वर्षों से बिहार के लोग उनके व्यवहार को देख रहे हैं। किशोर ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को प्रेस से बातचीत करने और सार्वजनिक कार्यक्रमों को संबोधित करने से रोककर उन्हें लोगों की नजरों से बचाने की कोशिश की जा रही है।

बिहार विधानपरिषद में एक बार फिर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक देखने को मिली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार विधानपरिषद में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष की नेता राबड़ी देवी के बीच एक बार फिर नोकझोंक देखने को मिली। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी से कहा कि रानाीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी होने के सिवा उनका कोई महत्व नहीं है। जनता दल यूनाइटेड (जद-यू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर मंगलवार तब नाराज हो गये, जब विधानपरिषद में राजद के सदस्य हरे रंग के बैज लगाकर पहुंचे, जिन पर नारे लिखे थे कि राज्य में वंचित जातियों के लिए 'तेजस्वी सरकार' ने आरक्षण बढ़ा दिया था, लेकिन भाजपा के सत्ता में लौटने के बाद इसे छीन लिया गया। हरा रंग राजद के झंडे का रंग है।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव तब उपमुख्यमंत्री थे, जब 2023 में कानून पारित कर आरक्षण बढ़ाया गया था। हालांकि, कुछ महीनों बाद पटना उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया था। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अपने पूर्व सहयोगी द्वारा इस लोकलुभावन कदम का श्रेय लेने के प्रयास से स्पष्ट रूप से नाराज नजर आये। उन्होंने विधानपरिषद में एक (राजद) सदस्य को खड़ा होने को कहा, ताकि बैज और उस पर लिखे नारे स्पष्ट रूप से नजर आएं। मीडिया दीर्घा की ओर देखते हुए नीतीश कुमार (70) ने कहा, इस तमाशे को देखिए। यह आप केवल इसी पार्टी में यह देख सकते हैं।

राबड़ी देवी अपनी पार्टी का मजाक उड़ाये जाने के खिलाफ विरोध जताने के लिए खड़ी हुईं, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे कहा, आप इससे दूर ही रहिए। यह पार्टी आपकी नहीं, आपके पति की है। सदन में हाल में कई बार कुमार और राबड़ी देवी के बीच वाकयुद्ध देखने को मिला है। मीडिया दीर्घा और सत्ता पक्ष के अपने सहयोगियों की ओर देखते हुए कुमार ने कहा, इस बेचारी महिला को उनके पति ने ऐसे समय में आगे बढ़ाया, जब वह मुसीबत में थे। उल्लेखनीय है कि राबड़ी देवी 1997 में मुख्यमंत्री बनी थीं, जब चारा घोटाले में सीबीआई द्वारा आरोपपत्र दाखिल किये जाने के बाद उनके पति लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। संयोगवश, प्रसाद के पूर्व सहयोगी कुमार ने एक साल पहले ही उनसे अलग होकर भाजपा के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी, जिसकी परिणति 2005 में राजद को सत्ता से उखाड़ फेंकने के रूप में हुई। तब से दोनों धुर विरोधी दलों के बीच दो अल्पकालिक गठबंधन हुए हैं। हाल में, कुमार बार-बार याद दिलाते रहे हैं कि कैसे राजद सुप्रीमो ने राज्य की बागडोर अपनी गृहिणी पत्नी को सौंप दी, ताकि वह छद्म रूप से शासन जारी रख सकें।

अभिनेता सोनू सूद की पत्नी और दो अन्य सड़क हादसे में घायल

नागपुर/भाषा। महारानई के नागपुर शहर में हुए एक सड़क हादसे में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की पत्नी सोनाली और दो अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि हादसा सोमवार रात करीब 10.30 बजे हुआ। उन्होंने बताया कि सोनाली सूद अपनी बहन और भांजे के साथ जिस कार में यात्रा कर रही थीं, वह वर्धा रोड वायाडक्ट पुल पर एक ट्रक से टकरा गई। अधिकारी के अनुसार, हादसे में घायल तीनों लोगों को नागपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया।

दिशा सालियान के पिता ने आदित्य ठाकरे, अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने मंगलवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) को एक शिकायत सौंपकर 2020 में अपनी बेटी की मौत के सिलसिले में शिवसेना (उबाठा) विधायक आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। सालियान ने अपने वकील के साथ दक्षिण मुंबई में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) के कार्यालय का दौरा किया। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी की जून 2020 में हुई मौत की परिस्थितियों की नये सिरे से जांच कराने के अनुरोध के साथ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था।

उच्च न्यायालय में दायर याचिका में सालियान ने कहा है कि दिशा के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मामले में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई। याचिका में आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का अनुरोध किया गया है। इस पर अप्रैल के पहले सप्ताह में सुनवाई होने की संभावना है। वहीं, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब अदालत में देंगे।

जेसीपी को लिखित शिकायत सौंपने के बाद सालियान ने संवाददाताओं से कहा, मुझे अपनी बेटी के लिए न्याय की उम्मीद है। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। सालियान के वकील ने कहा कि आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए मुंबई पुलिस को एक लिखित शिकायत सौंपी गई है।

दपरे के 5 कर्मचारियों को सुरक्षा पुरस्कार मिले

महाप्रबंधक ने सम्मानित किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हुब्बली/दक्षिण भारत। दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) के महाप्रबंधक मुकुल शरण माथुर ने मंगलवार को यहां रेल सौधा स्थित सम्मेलन कक्ष में विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ सुरक्षा बैठक की। रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने पर महत्त्वपूर्ण चर्चा के बाद माथुर ने पांच कर्मचारियों (हुब्बली मंडल से एक, बेंगलूरु व मैसूरु मंडल से दो-दो) को सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया।

ये पुरस्कार उनकी ड्यूटी के दौरान सतर्कता, अप्रिय घटनाओं को टालने में योगदान और पिछले महीनों में ट्रेन संचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने की सराहना में दिए गए।

हुब्बली मंडल से शिवाजी एल पवार, बेंगलूरु मंडल से कैलाश प्रसाद मीणा और एचएस महेश, मैसूरु मंडल से जेबी लोहित और अबू सलिया को सम्मानित किया गया।

मुकुल शरण माथुर ने कर्मचारियों की त्वरित सोच और सुरक्षा के प्रति समर्पण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 'सुरक्षा पहले और हमेशा सुरक्षा' दपरे की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।

स्टालिन ने भाषा विवाद पर कहा, इस बारे में घोषणा की जाएगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कथित रूप से भाषा थोपने और वित्तीय अन्याय को लेकर मंगलवार को केंद्र की आलोचना की और सटीक पहल के जरिए इस मुद्दे का हमेशा के लिए समाधान करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में जल्द ही घोषणा करेंगे। स्टालिन ने विधानसभा में भाषा नीति पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार उन विधायकों से पूरी तरह सहमत है जिन्होंने द्वि-भाषा नीति का दृढ़ता से समर्थन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''तमिलनाडु की द्वि-भाषा नीति में तमिल और अंग्रेजी दो भाषाएं हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।'' उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्टालिन ने अपने हालिया बयान की भी याद दिलाई कि यदि केंद्र हिंदी सीखने के लिए धनराशि जारी करता है, तो हमें उस पैसे की आवश्यकता नहीं है; हम तमिल भाषा की रक्षा करेंगे। 2,000 करोड़ रुपये क्यों? केंद्र 10,000 करोड़ रुपये भी दे तो हम 3-भाषा नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''मैं दोहराता हूं; यह धन/कोष से संबंधित मुद्दा नहीं है; यह हमारे समाज (तमिल लोगों द्वारा सामना की जाने वाली जातीयता/समस्या) के समक्ष एक समस्या है। यह हमारे युवाओं, छात्रों, तमिल जाति और तमिल भाषा की सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है।'' उन्होंने याद दिलाया कि 23 जनवरी 1968 को सदन में

द्वि-भाषा नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, जब सी एन अन्नादुरई मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि यह नीति अन्नादुरई की देन थी।

स्टालिन ने कहा, ''हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। हमारा कहना है कि ये दो भाषाएं पर्याप्त हैं।'' उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी भाषा को सीखने के इच्छुक व्यक्ति के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम किसी ऐसी वर्चस्ववादी भाषा की भी अनुमति नहीं देते जो तमिल को नष्ट करने का इरादा रखती हो। इसीलिए हम दो-भाषा नीति का पालन करते हैं।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों सहित कई राज्यों को अब एहसास हो गया है कि तमिलनाडु की भाषा नीति और उसका पालन करने की प्रतिबद्धता सही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, हिंदी भाषा को थोपना सिर्फ एक भाषा को थोपना नहीं है; यह संस्कृति का विनाश होगा, इसीलिए हम दृढ़ हैं। भाषा थोपने के माध्यम से वे राज्यों, राज्यों की भाषाओं और एक समाज पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर पूरी तरह से विराम लग जाना चाहिए। वे भाषा थोपकर और वित्तीय अन्याय कर रहे हैं क्योंकि वे राज्यों को अपने बंधुआ गुलामों का क्षेत्र मानते हैं।

स्टालिन ने कहा, ''इसलिए, भारत के संघवाद की रक्षा करने और राज्य की स्वायत्तता हासिल करने के लिए, हमें सटीक पहल करने की मजबूरी है।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमिल भाषा की रक्षा की जा सकती है और तमिल लोगों का विकास तभी हो सकता है जब राज्य की स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए और राज्य के अधिकार स्थापित किए जाएं। स्टालिन ने कहा कि वह जल्द ही इस संबंध में घोषणा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता के पलानीस्वामी दिल्ली गए हैं और अपनी यात्रा के दौरान उन्हें भाषा नीति का मुद्दा उठाना चाहिए। इससे पहले, इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हुए द्रमुक विधायक एन एजिलन ने कहा कि आधिकारिक भाषा नियम 1976 तमिलनाडु की दो-भाषा नीति का समर्थन करता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि तमिलनाडु राज्य को नियमों के इस्तेमाल से छूट दी गई है।

सेल ने सर्वश्रेष्ठ संयंत्रों, कर्मचारियों को कॉरपोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने यहां आयोजित एक समारोह में कॉरपोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 और 2024 का वितरण किया। यह पुरस्कार कंपनी के उन संयंत्रों एवं इकाइयों और कर्मचारियों को दिए गए, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान और प्रदर्शन किया। इस समारोह के दौरान 11 श्रेणियों में 25 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस्को इस्पात संयंत्र को 2022-23 और बोकारो इस्पात संयंत्र को 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ इस्पात संयंत्र का पुरस्कार दिया गया।

इसी तरह, सर्वश्रेष्ठ संयंत्र/इकाई (एकीकृत इस्पात संयंत्रों के अलावा) की श्रेणी में सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सेट) को 2022-23 के लिए और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (एमटीआई) को 2023-24 के लिए सम्मानित किया गया। सेल कॉरपोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 में शुरू किए गए थे। ये पुरस्कार मुनाफा, लागत में कमी, काम में दक्षता, नयी प्रौद्योगिकी अपनाने, विपणन, नवाचार और सुरक्षा उपायों जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इस समारोह में सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

रेलवे बोर्ड ने यातायात व वाणिज्यिक विभाग के संवेदनशील पदों की पहचान की, कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने सभी 17 रेलवे जोन में यातायात परिवहन और वाणिज्यिक विभाग के कुछ राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की पहचान की है और उनके कार्यकाल को तीन साल तक सीमित कर दिया है। बोर्ड ने हाल ही में रेलवे जोन के सभी महाप्रबंधकों को संबोधित एक परिपत्र में कहा, पीसीओएम (प्रमुख वाणिज्यिक परिचालन प्रबंधक) के सचिव और पीसीसीएम (प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक) के काम की प्रकृति संवेदनशील है और इन पदों पर तैनात अधिकारियों की निष्ठा बेदाग होनी चाहिए।

इसमें कहा गया है, ऐसे अधिकारियों का कुल कार्यकाल तीन साल तक सीमित होना चाहिए। बोर्ड ने पीसीओएम के यातायात निरीक्षक और पीसीसीएम के वाणिज्यिक निरीक्षक के रूप में (औपचारिक या अनौपचारिक रूप से) काम करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए नियमित आवर्तन (रोटेशन) का निर्देश दिया, क्योंकि ऐसे अधिकारी महत्वपूर्ण मामलों में सहायता करते हैं।

परिपत्र में कहा गया है, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के यातायात निरीक्षक और डीआरडीसीएम (वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक) के वाणिज्यिक निरीक्षक के रूप में (औपचारिक या अनौपचारिक रूप से) काम करने वाले गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को भी रोटेट किया जाना चाहिए तथा कार्यकाल तीन साल तक सीमित होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के निजी सचिव और वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के निजी सचिव के रूप में तैनात कर्मचारियों को भी रोटेट किया जाना चाहिए।

बोर्ड ने क्षेत्रीय रेलवे से 30 अप्रैल, 2025 तक आवश्यक बदलाव करने का आग्रह किया है।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पी. प्रकाश बाबू ने उपराज्यपाल से मुलाकात की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी. प्रकाश बाबू ने 25 मार्च को राज निवास में पुडुचेरी के उपराज्यपाल और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के मुख्य रेक्टर के. कैलाशनाथन से शिष्टाचार भेंट की।

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पांडिचेरी विश्वविद्यालय की विजिटर के रूप में हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की संविधि 1(ए) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके प्रोफेसर फणीति प्रकाश बाबू को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। तदनुसार, प्रोफेसर फणीति प्रकाश बाबू ने पिछले 17 मार्च को पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया।

पति की हत्या के आरोप में पत्नी और सास गिरफ्तार

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक के बेंगलुरु में अपने पति एवं रियल एस्टेट एजेंट की हत्या करने के आरोप में उसकी पत्नी और सास को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बतायचा कि बीजीएस लेआउट में एक निर्माणाधीन इमारत के पास 37 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट का शव कुछ दिन पहले पाया गया था। पुलिस ने बताया कि अपने पति लोकनाथ सिंह की हत्या के आरोप में पत्नी यशस्विनी (19) और उसकी मां हेमा भाई (37) को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। सोलादेवानाहल्ली में 22 मार्च को सिंह की हत्या की गई थी।

पुलिस के अनुसार, यशस्विनी ने कुछ महीने पहले अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ सिंह से शादी की थी। यशस्विनी को बाद में पता चला कि सिंह का विवाहेतर संबंध है और इस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। इसके बाद वह अपने माता-पिता के घर वापस चली गई।

सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की हत्या पर तमिलनाडु पुलिस प्रमुख और कलेक्टर को एनएचआरसी का नोटिस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को कहा कि उसने तमिलनाडु के पुलिस प्रमुख और तिरुनेलवेली जिले के कलेक्टर को उन मीडिया रिपोर्टों पर नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि चार व्यक्तियों के एक समूह द्वारा एक सेवानिवृत्त पुलिस उपनिरीक्षक की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। एनएचआरसी ने बताया कि उसने संबंधित घटना के बारे में मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया।

आयोग ने अपने एक बयान में कहा कि पीड़ित व्यक्ति इलाके में वक्फ भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा था और उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी।

बयान के अनुसार, पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि वह (पुलिस) उनके (आरोपियों के) साथ मिली हुई है।

आयोग ने कहा है कि यदि समाचार रिपोर्ट सत्य पाई जाती है तो यह स्पष्ट है कि पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। बयान में कहा गया है कि एनएचआरसी ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक और तिरुनेलवेली के कलेक्टर से चार हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस की लापरवाही के कारण हत्या की यह घटना हुई।

कराटे में महारत हासिल करने वाले अभिनेता शिहान हुसैनी का निधन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। कराटे और तीरंदाजी में महारत हासिल करने वाले अभिनेता शिहान हुसैनी का रक्त कैंसर से लंबे समय तक जूझने के बाद चेन्नई स्थित एक निजी अस्पताल में मंगलवार तड़के निधन हो गया। परिजनों ने यह जानकारी दी। वह 60 वर्ष के थे। शिहान हुसैनी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्हें मूर्तिकारी, चित्रकारी, मार्शल आर्ट और तीरंदाजी में विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और बेटी हैं। परिवार ने उनके फेसबुक पोस्ट के जरिए यह दुखद समाचार साझा किया।

उन्होंने लिखा, ''मुझे यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि हुसैनी हमें छोड़कर चले गए।'' तमिलनाडु तीरंदाजी संघ (टीएएटी) के प्रवक्ता अश्विन कुमार अय्यर ने कहा, टीएएटी के संस्थापक और महासचिव शिहान हुसैनी का देर रात एक बजकर 45

मिनट पर निधन हो गया। हुसैनी ने ल्यूकेमिया (रक्त कैंसर) के बावजूद अपने शरीर को चिकित्सा अनुसंधान के लिए दान करने का निर्णय लिया। अय्यर ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''चिकित्सक तय करेंगे कि कौन सा अंग निकाला जा सकता है और उसके बाद शव को उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा।'' अभिनेता के पार्थिव शरीर को उनके विद्यार्थियों और अन्य लोगों के अंतिम दर्शन के लिए शाम सात बजे तक बेसेंट नगर स्थित उनके घर पर रखा जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मदुरै ले जाया जाएगा।

परिवार ने अपील की, जो कोई भी शिहान को श्रद्धांजलि देने उनके घर आ रहे हैं, कृपया अपनी पोशाक में आएं (कोई भी रंग ठीक है)। यदि संभव हो तो अपने धनुष और बाण के साथ आएं और कुछ तीर चलाएं... सभी तीरंदाज शाम पांच बजे कुछ तीर चलाएं। सभी कराटे प्रस्तुतकर्ता दोपहर तीन बजे एकत्र हों और कराटे में अपनी दक्षता का प्रदर्शन करें।

अय्यर ने कहा कि तमिलनाडु में तीरंदाजी की स्थापना और विकास के पीछे शिहान हुसैनी का बड़ा योगदान था और उनके अथक प्रयासों से राज्य में तीरंदाजी के कई चैंपियन तैयार हुए जिन्होंने राज्य और देश का गौरव बढ़ाया।

हुसैनी की पहचान कराटे प्रशिक्षक के रूप में बनी थी। उन्होंने 101 कारों से अपने हाथ को कुचलवाकर, 5,000 टाइलें और 1,000 ईंटें तोड़कर अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कमल हासन की 'पुन्नागई मन्नन' (1986) से की और रजनीकांत की 'वेलाइकरन' सहित कई फिल्मों में काम किया।

निजता की आड़ में आरटीआई को कमजोर कर रही है सरकार : राहुल

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार निजता की सुरक्षा की आड़ में सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत सूचनाओं के सामने आने पर अंकुश लगा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वह 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगियों के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे और आगे कदम उठाएंगे। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं ने राहुल गांधी से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में उनसे मुलाकात की। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''आज, मुझे संसद में सामाजिक कार्यकर्ताओं, संपादकों, शोधकर्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों के एक समूह से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने डिजिटल निजी डेटा संरक्षण अधिनियम, विशेष रूप से आरटीआई अधिनियम के दायरे पर इसके प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की।'' उन्होंने कहा कि यह कानून, निजता की सुरक्षा के बहाने सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच को कम करता है, जो नागरिकों और पत्रकारों के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक है।

द्रमुक सदस्य ने रास में की आपदा प्रबंधन के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की वजह से देश में, खास कर तटीय राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं जाने का जिक्र करते हुए राज्यसभा में मंगलवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के आर गिरिराजन ने ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने तथा मंत्रालय के लिए अलग बजट नियत करने की मांग की। आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 में उच्च सदन में हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस के नीरज डांगी ने इस विधेयक को आधा-अधूरा बताते हुए कहा कि इसमें राज्यों के अधिकार एक तरह से कमतर करने का प्रयास किया गया है वहीं तृणमूल कांग्रेस के रीताव्रता बनर्जी ने इस संशोधन विधेयक को गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की।

उच्च सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 को चर्चा करने एवं पारित करने के लिए रखा। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा ले रहे द्रमुक सदस्य आर गिरिराजन ने कहा कि विधेयक में विभिन्न मुद्दों को उपेक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि ''इसमें हमारे आपदा प्रबंधन ढांचे को स्पष्ट और मजबूत करने के बजाय केंद्रीकरण पर अधिक ध्यान दिया गया है जबकि आपदा प्रबंधन की स्थिति में विकेंद्रीकरण अधिक जरूरी होता है।''

उन्होंने कहा कि आपदा राहत को कानूनी अधिकार का रूप दिया जाना चाहिए क्योंकि यह जरूरी है। द्रमुक सदस्य ने कहा कि विधेयक में आपदा की रोकथाम और आंकड़ों के संग्रह के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्यों के अधिकारों की इस विधेयक में उपेक्षा की गई है और एक तरह से उनकी स्वायत्तता को खत्म करने का प्रयास किया गया है।

गिरिराजन ने कहा कि केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में इस विधेयक में अपेक्षित प्रावधान नहीं किए हैं जबकि अब तो इन दुष्प्रभावों का सामना अक्सर करना होगा। उन्होंने मांग की कि आपदा प्रबंधन के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए जो न केवल आपदा प्रबंधन को देखे बल्कि पुनर्वास भी उसकी प्राथमिकता हो। उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय का अलग बजट होना चाहिए। उन्होंने मांग की सार्वजनिक क्षेत्र की लाभकारी एवं निजी कंपनियों को उनके कुल सीएसआर कोष का तीन फीसदी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष में देना अनिवार्य किया जाए।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा में अपनी बात रख रहे कांग्रेस के नीरज डांगी ने कहा कि यह विधेयक अपूर्ण है क्योंकि इसमें स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया है। डांगी ने आरोप लगाया कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए अहम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा शमन कोष जैसे निकायों के संचालन की ओर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि असली आपदाएं तो कुछ और ही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी ही एक आपदा कोविड महामारी है जिसका प्रबंधन करने में सरकार विफल रही। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों के आपत्ति जताने पर डांगी ने कहा कि कोविड 19 जैसी महामारी अगर देश में नहीं आई होती तो शायद इस विधेयक पर अभी चर्चा नहीं होती।

डांगी ने कहा कि कोविड काल में 'पीएम केयर फंड' की स्थापना की गई लेकिन इस कोष को आरटीआई के दायरे से क्यों मुक्त रखा गया? डांगी ने कहा विधेयक में डेटाबेस बनाने की बात कही गई है जो केवल दिखावा है।

सरकार तो पीएम केयर फंड का विवरण छिपाती है तो वह डेटाबेस केवल बनाएगी। उन्होंने आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का सुझाव दिया। चर्चा में हिस्सा ले रहे भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन की मुख्यत: जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और केंद्र इसमें नोडल एजेंसी की भूमिका निभाता है।

अभिनेत्री रान्या राव ने हवाला का इस्तेमाल करने की बात स्वीकारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/भाषा। सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार कन्नड अभिनेत्री हर्षवर्धनी रान्या उर्फ रान्या राव ने (सोना) खरीद के लिए हवाला का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की है। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को एक विशेष अदालत के समक्ष यह दलील दी। इस बीच, अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों की विस्तृत सुनवाई के बाद अभिनेत्री की जमानत याचिका पर अपना फैसला 27 मार्च तक सुरक्षित रख लिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राव ने सोने की खरीद के लिए हवाला का उपयोग करने की बात स्वीकार की है, जो उनके खिलाफ मामले को मजबूत करता है। सुनवाई के दौरान राव की अधिवक्ता किरण जावली ने उनकी रिहाई के लिए दलील पेश कीं, जबकि राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की अधिवक्ता मधु राव ने धन के अवैध हस्तांतरण में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दर्शाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए।

कानूनी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 को लागू किया है, जो न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या के पास से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन मार्च को दुबई से लौटते समय 12.56 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया गया।

डीआरआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इसके बाद उनके आवास पर तलाशी ली गई, जहां अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की।

विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि में नारीशक्ति की अहम भूमिका

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/एजेन्सी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे देश और प्रदेश का इतिहास वीरता और त्याग से भरा हुआ है। कालीबाई भील, रानी पद्मिनी, मीराबाई, पन्नाधाय और अमृता देवी जैसी महान महिलाओं ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ संकल्प का परिचय देकर अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि परिवार की नींव को मजबूत करने वाली महिलाएं हमारे समाज की धुरी हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है और आधी आबादी को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है।

शर्मा मंगलवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौरवशाली सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए इस बार राजस्थान दिवस अंग्रेजी कलैण्डर के स्थान पर भारतीय पंचाग की तिथि नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (30 मार्च) को मनाया जा रहा है। इसी दिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को मिलाते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। इस वर्ष भी रेवती नक्षत्र इंद्रयोग का वही संयोग बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी को नारायणी का दर्जा प्राप्त है। नारी का सम्मान समाज और देश-प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है, इसीलिए राजस्थान दिवस समारोह का पहला कार्यक्रम हमने मातृशक्ति को समर्पित किया है।

मुख्यमंत्री ने आधी आबादी को दी बड़ी सौगातें

मुख्यमंत्री शर्मा ने महिला सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं की चयनित लाभार्थियों से संवाद किया और योजनान्तर्गत देय सहायता से लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री ने अति कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन में दूध 15 ग्राम से 25 ग्राम देने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए। महिला समूहों को लगभग 100 करोड़ रुपए की आजीविका संवर्धन निधि का हस्तान्तरण और 5 हजार महिलाओं को इंडेक्शन कुक टॉप का वितरण किया गया। साथ ही, उन्होंने स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के अंतर्गत 164 छात्राओं को चयन पत्र का वितरण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीविका मेला शुरू किया गया है। शर्मा ने गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अन्तर्गत 31 हजार 790 बालिकाओं को 13.16 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसी क्रम में हमने आज विभिन्न जिलों के 36 महिला महाविद्यालयों में ये सुविधा प्रारंभ की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बर्तन बैंक योजना और सोलर दीदी के दिशा-निर्देश भी जारी किए।

प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तीकरण के लिए किए अभूतपूर्व निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र एवं राज्य की सरकारों ने महिला कल्याण के लिए अभूतपूर्व निर्णय किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान कर उनका सशक्तीकरण किया है। साथ ही, तीन तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर मुस्लिम बहनों का जीवन भी तबाह होने से बचाया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान संचालित कर, बैंक खाते खुलवाकर, उज्वला सिलेंडर देकर तथा जल जीवन मिशन के जरिए गांव-गांव में नल से जल पहुंचाकर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। शर्मा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए हमने सरकार बनते ही सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया। साथ ही, बालिकाओं को शिक्षा एवं संबल उपलब्ध कराने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की। अब इसके तहत गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख के स्थान पर डेढ़ लाख रुपए का सेविंग बॉण्ड मिलेगा।

मानवीय मूल्यों के साथ प्रौद्योगिकी विकास के लिए आगे बढें युवा : बागडे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोटा/एजेन्सी। राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ किसनराव बागडे ने प्राचीन भारत की मेधा, जीवन मूल्यों और पुरा वैभव की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए युवाओं का आह्वान किया है कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देश का चित्र बदलने का महती दायित्व उनके कंधों पर है और अपने ज्ञान का उपयोग केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि नवाचार और उद्यमिता के लिए भी करते हुए वे मानवीय मूल्यों के साथ प्रौद्योगिकी विकास के लिए आगे बढें।

बागडे मंगलवार को यहां राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के चतुर्दश दीक्षांत समारोह में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में भारत की आजादी को एक शताब्दी पूर्ण हो रही है। इस समय तक भारत सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित करे, ऐसे हमारे प्रयास होने चाहिए। सबका साथ, सबका विकास ही हमारा ध्येय बने। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देश का चित्र बदलने का महती दायित्व उनके कंधों पर है। आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट आफ थिंग्स और रोबोटिक्स जैसी तकनीको का है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के लिए भी करें।

राज्यपाल ने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत अग्रणी रहा है। पर यह विडम्बना रही है कि यूरोपीय देशों ने हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विरासत को अपना बनाकर पेश किया। भारत की ज्ञान परम्परा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर आधारित है। इसमें बौद्धिक क्षमताओं के संवर्द्धन पर अधिक जोर है जिसके परिणाम लगभग 15 साल बाद परिलक्षित होंगे। यह समय ज्ञान संचार का है। केवल पाठ्यपुस्तकों को पढ़कर जीवन में सफल नहीं हो सकता।

इस अवसर पर 9521 डिग्रियों, एक कुलाधिपति एवं एक कुलपति स्वर्ण पदक एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 20 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 36 पीएचडी डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी और बौद्धिक क्षमताओं का विस्तार करते हुए भारत को विश्वगुरू के पद पर पुनःआसीन करने का आह्वान किया।

देश में एक साथ चुनाव से होगा विकास, राजनीतिक वैमनस्यता में होगी कमी : बंसल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/एजेन्सी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा है कि देश में एक साथ चुनाव होते है तो राजनीतिक वैमनस्यता कम होगी और विकास ज्यादा होगा।

बंसल मंगलवार को जयपुर में ..एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान.. को लेकर युवा, छात्र एवं नवमतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन सरकारों पर केवल विकास का ही दबाव होगा, युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि होता है लेकिन पिछले 30 सालों से लगातार हर साल चुनाव प्रक्रिया चलने से देश के मतदाता में कहीं ना कहीं निरसता आई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीबन 40 प्रतिशत लोग मतदान ही नहीं कर रहे। उन्होने कहा कि एक साथ लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव कराने और इसी दौरान 100 दिनों में अन्य निकायों के चुनाव संपन्न कराने से मतदाता की निरसता भी दूर होगी और एक स्वस्थ एवं मजबूत लोकतंत्र की ओर देश बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर बार बार चुनाव कराने से आर्थिक बोझ भी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक राष्ट्र एक चुनाव महत्वपूर्ण कदम है। देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए और व्यर्थ के खर्चे से बचने के लिए हम सभी को एक मुखी होकर इस जन जागृति अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से संयुक्त संसदीय कमेटी के सामने एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में प्रस्ताव जाना चाहिए। यह अभियान सर्वव्यापी अभियान बनाना चाहिए।

श्री राठौड ने कहा कि केन्द्र सरकार ने दो सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि लोकसभा

भारतीय सीमा में आई हुमायरा को वापस पाकिस्तान भेजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीगंगानगर/एजेन्सी। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ सेक्टर में भारतीय सीमा में आई एक महिला को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मंगलवार को पाकिस्तानी रेंजर्स के सुपुर्द कर दिया।

बीएसएफ के सूत्रों ने बताया कि 33 वर्षीया हुमायरा को अनूपगढ़ सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की बिंजौर पोस्ट से अपराह्न करीब तीन बजे पाकिस्तानी रेंजर्स के सुपुर्द किया गया। हुमायरा वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी। वह भारत में ही रहने की इच्छुक थी। वह भारत में शरण चाहती थी। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के जिला कैच में तुरबत तहसील की हुमायरा के एक बेटा और एक बेटी है। वह 17 मार्च की सुबह अनूपगढ़ सेक्टर की विजेता पोस्ट के नजदीक पिलर नंबर 362/28 से अंतरराष्ट्रीय सीमा अवैध रूप से पार करके भारतीय क्षेत्र में आ गई थी। जिसे बीएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया। खुफिया एजेंसियों द्वारा उससे लम्बी पूछताछ के बाद उसे संदेह से परे माना। शनिवार को हुमायरा को अनूपगढ़ सेक्टर से लगती पाकिस्तान सीमा पर वापस भेजने के लिए ले जाया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स से फ्लैग मीटिंग की गई। फ्लैट मीटिंग में पाकिस्तानी रेंजर्स ने हुमायरा को लेने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले किसी अधिकारी से अधिकार पत्र लाकर दें। लिहाजा एक उच्च अधिकारी का अधिकार पत्र मिलने पर आज उसे बिंजौर पोस्ट पर ले जाया गया, जहां से पाकिस्तानी रेंजर्स उसे लेकर चले गए।

मुलाकात

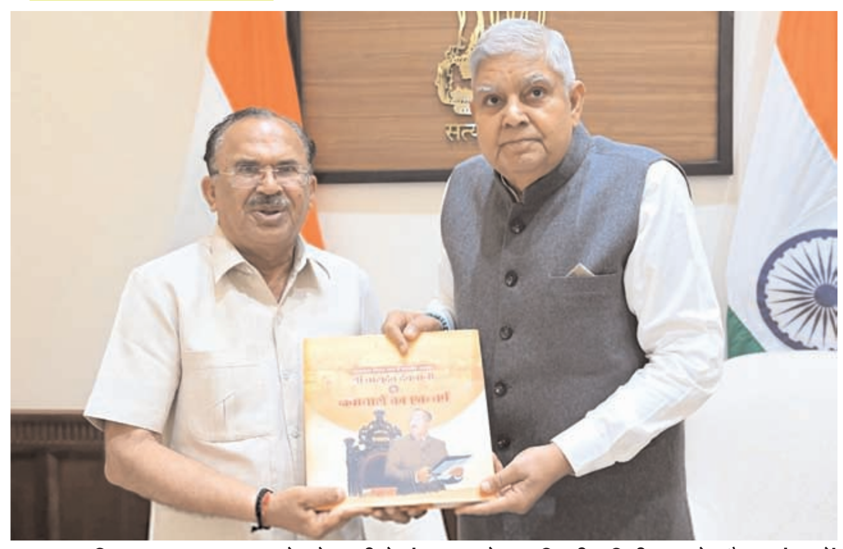

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को एक दिवसीय दिल्ली यात्रा के दौरान संसद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार मुलाकात की। राजस्थान विधानसभा में एक वर्ष में किये गये नवाचारों पर आधारित पुस्तक '' राजस्थान विधान सभा में माननीय अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नवाचारों का एक वर्ष'' की प्रति देवनानी ने उपराष्ट्रपति धनखड को भेंट की।

फ्रीबीज बन्द करने के लिए जल्द कराई जानी चाहिए सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना : गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/एजेन्सी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर रेवड़ी (फ्रीबीज) बन्द करनी हैं तो जल्द सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए।

गहलोत ने मंगलवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। यह सभी गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में सरकारों के पास ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है जो परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत स्थिति को बता सके। इस कारण ऐसी योजनाएं नहीं बनाई जा सकती जो अलग-अलग वर्ग की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्होंने अपना जीवन चलाने के लिए धन अर्जित करना बेहद आवश्यक है परन्तु कई परिवारों में ऐसी विकट

परिस्थितियां होती हैं कि वो चाहकर भी एक सामान्य रहन-सहन के लिए आवश्यक धन अर्जित कर सकें। इसका कारण बीमारी, गरीबी, स्किल की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी आदि हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के अनेक विकसित और विकासशील देशों में सभी जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाकर साप्ताहिक और मासिक तौर पर एक निश्चित राशि दी जाती है क्योंकि वहां अलग-अलग वर्ग का बेहतर डाटा उपलब्ध है। इससे वहां चुनावी लाभ के लिए फ्रीबीज की घोषणा भी नहीं करनी पड़ती।

गहलोत ने कहा कि पूरे देश में एक जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना होने पर अलग-अलग राज्यों पर अनावश्यक दबाव भी नहीं पड़ेगा। राजस्थान में राजस्थान न्यूनतम इनकम गारंटी एक्ट से इस दिशा में एक कदम बढ़ाया गया था। नई सरकार ने इस कानून को ठीक से लागू नहीं रखा परन्तु हमारे समय भी सही डाटा की व्यापक तौर पर उपलब्धता इसमें भी एक चुनौती थी। उन्होंने कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा कराई गई सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर ही वर्तमान में केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत जैसी तमाम योजनाएं चल रही हैं। अब वक्त सामाजिक सुरक्षा कानून का है जिससे अमीर-गरीब की खाई कम हो एवं देश में फ्रीबीज के नाम पर हर राजनीतिक पार्टी द्वारा की जा रहीं घोषणाएं भी रुक सकें।

कांग्रेस सरकार ने निकाय, पंचायतों के गठन में किया था अधिकारों को दुरूपयोग : राठौड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/एजेन्सी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए निकायों और पंचायतों का गठन किया था।

राठौड़ ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में कहा कि कांग्रेस ने जनसंख्या के अनुपात में समान वर्गीकरण नहीं किया, कहीं एक वार्ड में 500 मतदाता तो कहीं दूसरे वार्ड में तीन हजार मतदाताओं को शामिल किया गया। कहीं किसी पंचायत में 400 मतदाता थे तो कहीं सात हजार मतदाताओं की एक पंचायत बना दी। यह पूरी तरह से गलत था और कांग्रेस ने जनता के साथ अन्याय किया था। ऐसे में डोटासरा को बोलने से पूर्व अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री डोटासरा को अध्ययन करना चाहिए कि भारत में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' नयी अवधारणा नहीं है। देश के पहले आम चुनाव भी इसी अवधारणा के साथ हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने धारा 356 का दुरूपयोग करते हुए कई राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया, लोकसभा को भंग कर दिया था। इसके बाद से अलग-अलग चुनाव होने लगे।

राठौड़ ने कहा कि भारत ही नहीं, कई देशों में भी एक साथ चुनाव कराए जाते हैं। अगर भारत में एक साथ चुनाव होते हैं तो देश विकास के मार्ग पर चलेगा। देश में बार-बार चुनाव होने और आचार संहिता लागू होने से विकास बाधित होता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रयास है कि एक साथ चुनाव हों, पंचायतों का पुनर्गठन हो, मतदाताओं के आधार पर परिसीमन हो। उन्होंने कहा कि यह होगा और श्री डोटासरा देखते रह जाएंगे। पंचायत चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चुनाव आयोग अपना-अपना कार्य कर रहे हैं।

राठौड़ ने कहा कि पार्टी में संगठन विस्तार की प्रक्रिया चल रही है। भाजपा में संगठन विस्तार की निर्धारित प्रक्रिया है, मंडल में जिलाध्यक्ष से राय लेकर समिति का गठन किया जाता है, जिले में प्रदेश अध्यक्ष से राय ली जाती है और राज्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष से राय के बाद संगठन विस्तार किया जाता है। फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद राज्य की प्रक्रिया चलेगी।

इकतीस लाख रूपये की ठगी के मामले का आरोपी कानपुर से गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/एजेन्सी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बिंदायका थाना पुलिस ने जयपुर निवासी एक व्यपारी से 31 लाख रूपये की ठगी करने के मामले में आरोपी को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि परिवादी जयपुर के बिंदायका निवासी दिनेश फतेहपुरिया ने पुलिस में दिये परिवाद में कहा कि उसकी फर्म अरिहंत का एचडीपीई प्लास्टिक पाईप का व्यवसाय है। आरोपी संदीप कंसल उर्फ संदीप अग्रवाल निवासी दिल्ली ने वर्ष नौ जनवरी 2020 को सरकारी टेंडरों का लालच देकर उसको 31 लाख पांच हजार 996 रूपये का एचडीपीई खरीद सप्लाई करने का भुगतान किया।

रिपोर्ट में बताया कि इसके बाद आरोपी संदीप ने अपना जयपुर का कार्यालय बंद कर दिया, वह जो पाईप खरीदा था वह भी नही सप्लाई किया। परिवादी के बार बार तकाजा करने पर भी आरोपी ने अपनी राशि नहीं लौटाई। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुये विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा आसूचना संकलन कर तथा तकनीकी सहायता प्राप्त कर आरोपी संदीप को सोमवार शाम को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार कर जयपुर लाई है।

पेपर माफिया को शिकंजे में लेने के लिए सरकार को गंभीर होने की जरुरत : डोटासरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/एजेन्सी। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश में पेपर माफिया पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार को इसे और गहराई से लेकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनर्रावृत्ति नहीं हो, तभी समाज को नहीं दिशा दी जा सकती है।

डोटासरा मंगलवार को यहां प्रेस कांफ्रेस में एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेपर माफिया सक्रिय थे

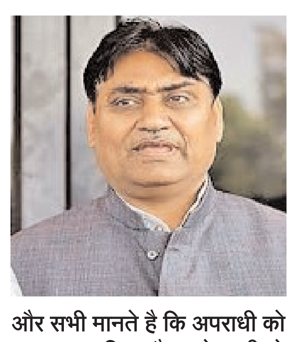

और सभी मानते है कि अपराधी को पकड़ना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए लेकिन पूरे सिस्टम में कोई ब्यूरोक्रेट दोषी नहीं है क्या, कोई अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है क्या। नेताओं के ये रोजाना टिप्पणी करते रहते है, टिप्पणी की बजाय कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी मामले में नेता शामिल हैं तो उसे पकड़ों, अगर ब्यूरोक्रेट से गलती हुई है तो उसे भी पकड़ों। उन्होंने कहा कि लेकिन एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर तमाशा बनाकर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक-दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने से सिस्टम सुधरने वाला नहीं हैं। सरकार को ज्यादा गहराई से लेना चाहिए और पूरे पेपर माफिया को शिंकजे में लेने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनर्रावृत्ति नहीं हो, हम सब का यही उद्देश्य होना चाहिए तभी हम समाज को नई दिशा दे पायेंगे।

निर्माण अधूरा, नोएडा हवाई अड्डे से अप्रैल से व्यावसायिक उड़ानें शुरू होने की संभावना कम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ग्रेटर नोएडा/भाषा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अप्रैल में व्यावसायिक उड़ानें शुरू होने की संभावना कम है। इसकी वजह टर्मिनल बिल्डिंग का अधूरा निर्माण बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 मार्च को समीक्षा के दौरान हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने और सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी तय की थी।

इस महीने के अंत तक हवाई अड्डे के निर्माण कार्य की समीक्षा करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आ सकते हैं। ऐसे में हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब 15 मई तक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से व्यावसायिक उड़ान सेवाएं शुरू करने के लिए एयरोड्रम लाइसेंस मिलने की संभावना है। टर्मिनल का काम तेजी से चल रहा है, इसलिए शुरुआत में यात्रियों को विमान तक ले जाने के लिए छह एयरोब्रिज लगाए जाएंगे। यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एयरोब्रिज हवाई अड्डे पर एक ऐसा पुल है जो यात्रियों को सीधे टर्मिनल बिल्डिंग से विमान के दरवाजे तक ले जाता है। यह एक सुरंग जैसा रास्ता है, जिसके जरिये यात्री आसानी से विमान तक पहुंच सकते हैं। विमान से उतरते समय टर्मिनल में प्रवेश करने के लिए भी एयरोब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल टर्मिनल के प्रवेश द्वार का काम चल रहा है।

उन्होंने बताया कि घरेलू टर्मिनल का काम लगभग पूरा हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के काम में कुछ महीने लगेंगे। ढलाई आदि के काम में भी देरी होगी, इसलिए हवाई अड्डे पर पहले दिन से अंतरराष्ट्रीय सेवा शुरू होना मुश्किल है। अब पहले दिन से सिर्फ घरेलू और कार्गो उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में शुरुआत में हवाई अड्डे पर सिर्फ छह एयरोब्रिज ही लगाए जाएंगे। पहले यहां 10 एयरोब्रिज लगाए जाने थे, जो 'साइट' पर पहुंच चुके हैं। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस थाना बनाया जाना है। इसके लिए हवाई अड्डे के पास करीब एक हजार वर्ग मीटर जमीन प्रस्तावित है। जमीन नि:शुल्क देने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से पत्राचार किया गया, लेकिन हवाई अड्डे का निर्माण करा रही कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (वाईएपीएल) ने नि:शुल्क जमीन देने से इनकार कर दिया है। इस एक हजार वर्ग मीटर में पुलिस थाने के साथ डीसीपी- एयरपोर्ट का मुख्यालय बनाया जाना है। कंपनी ने जमीन के एवज में एक करोड़ रुपये की मांग की है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने प्रमुख सचिव (गृह) से मामले में निर्देश जारी करने की मांग की है। यमुना विकास प्राधिकरण की ओर से 21 मार्च को यह पत्र जारी किया गया है। थाने के साथ ही हवाई अड्डे के पास दो पुलिस चौकियों का भी निर्माण किया जा रहा है।

'एक राष्ट्र-एक चुनाव' संबंधी संयुक्त समिति का कार्यकाल मानसून सत्र तक के लिए बढ़ा

नई दिल्ली/भाषा। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले दो विधेयकों पर विचार करने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के अपना प्रतिवेदन सौंपने के लिए कार्यकाल मंगलवार को इस साल मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस संयुक्त समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद पीपी चौधरी ने समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा, जिसे सदन ने ध्वनमति से मंजूरी दी।

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024' और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' पर संसद की 39 सदस्यीय संयुक्त समिति विचार कर रही है। समिति को बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। इन विधेयकों को पिछले साल 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में नरेन्द्र मोदी सरकार ने 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और इसने अपनी रिपोर्ट में इस अवधारणा का जोरदार समर्थन किया था।

मानसून सत्र में आ सकता है आयकर विधेयक : वित्त मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि नया आयकर विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। उन्होंने सदन में वित्त विधेयक, 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। सीतारमण ने इस बात का उल्लेख किया कि 'आयकर विधेयक, 2025' पर प्रवर समिति विचार कर रही है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि विधेयक को संसद के आगामी मानसून सत्र में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने गत 13 फरवरी को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विधेयक पर विचार करने के लिए 14 फरवरी को 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बैजयंत पांडा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। विधेयक, जो आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है। यह कानूनी भाषा को भी सरल बनाएगा, ताकि करदाता प्रावधानों को आसानी से समझ सकें। विधेयक के अंतर्गत नये कर नहीं लगाए जाएंगे। इसके बजाय, यह विधेयक कर कानूनों को सरल बनाने, कानूनी जटिलताओं को कम करने और करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

शीर्ष अदालत ने लालकिले के जीर्णोद्धार से संबंधित 20 साल से भी अधिक पुरानी याचिका निस्तारित की

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने 17वीं सदी के मुगलकालीन स्मारक लाल किले के जीर्णोद्धार और संरक्षण के अनुरोध वाली दो दशक से अधिक पुरानी जनहित याचिका का मंगलवार को यह कहते हुए निस्तारण कर दिया कि उसकी विशेषज्ञ समिति ने अधिकांश निर्देशों का अनुपालन किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राजीव सेठी द्वारा 2003 में दायर की गयी इस याचिका को निस्तारित कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि स्मारक का संरक्षण अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार नहीं किया गया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि छह अगस्त 2004 को उसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक समेत नौ सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया था। पीठ ने कहा, ''तब से 20 साल बीत चुके हैं और हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि विशेषज्ञ समिति ने अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया है...। (लेकिन) अगर कुछ नहीं किया गया है या कुछ छोड़ दिया गया है, तो याचिकाकर्ता को नई याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है।'' शीर्ष अदालत ने कहा कि अगस्त 2004 में उसने न केवल एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, बल्कि स्मारक के संरक्षण के लिए व्यापक निर्देश भी जारी किए थे।

भारत को स्वतंत्र 'मीडिया उद्योग निकाय' की जरूरत है : सागरिका घोष

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की सदस्य सागरिका घोष ने मंगलवार को कहा कि भारत में पेशेवर प्रसारण और पत्रकारिता की निष्पक्षता के वैश्विक मानकों को बनाए रखने वाले एक ''स्वतंत्र मीडिया उद्योग निकाय'' की तत्काल आवश्यकता है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान पत्रकार से राजनेता बनीं सागरिका घोष ने यह भी कहा कि भारत के विविधता और बहुलवाद में निहित जीवंत लोकतंत्र'' को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन को वास्तव में ''विश्व स्तरीय'' बनाया जाना चाहिए।

राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की उपनेता सागरिका घोष ने कहा, ''आज, पेशेवर प्रसारण और पत्रकारिता की निष्पक्षता के वैश्विक मानकों को बनाए रखने वाले एक स्वतंत्र मीडिया उद्योग निकाय की तत्काल आवश्यकता है।'' उन्होंने कहा कि विज्ञापन-वित्तपोषित टेलीविजन समाचार का मॉडल तेजी से क्षीण हो रहा है और यही कारण है कि मीडिया अपने मूल लक्ष्य से भटक रहा है। उन्होंने कहा कि वह 'न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी' (जिसे अब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है) की सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इसमें ताकत और वैधानिक शक्ति का अभाव है। उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किए बिना उनकी मौत से जुड़े मामले का संदर्भ देते हुए कहा, चार साल पहले समाचार चैनलों ने एक फिल्म अभिनेता के खिलाफ एक प्रेरित अभियान चलाया था। आज वह फिल्म अभिनेता निर्दोष साबित हुआ है। आज वे सभी आरोप निराधार साबित हुए हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को मीडिया के जरिये जो अपमान मिला उसका हिसाब कौन देगा।

उन्होंने कहा, सवाल यह है कि समाचार मीडिया चैनलों को और अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह कैसे बनाया जा सकता है? मीडिया मालिकों को जल्द ही संसद में बुलाया जाएगा। पक्षपाती एंकर पत्रकारिता के लिए धब्बा हैं।'' उन्होंने दूरदर्शन को ''विश्व स्तरीय'' बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, नई मीडिया तकनीकें दुनिया को छोटा कर रही हैं।

भाजपा ने पुस्तक का हवाला देकर सोनिया गांधी और राहुल के इस्तीफे की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को एक पत्रकार की पुस्तक का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं- सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला किया और मांग की कि जब तक वे कथित इतालवी बिचौलिए ओत्तावियो क्वात्रोची के साथ अपने संबंधों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे देते, तब तक के लिए वे संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। भाजपा ने उस पत्रकार की पुस्तक का हवाला दिया है, जिसे कथित बोफोर्स घोटाले को उजागर करने का श्रेय दिया जाता है।

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा अपनी पुस्तक 'बोफोर्स गेट' में किए गए 'बड़े खुलासे' चिंताजनक हैं। भाटिया ने आरोप लगाया कि क्वात्रोची ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी के साथ अपनी निकटता का इस्तेमाल रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने में किया। भाजपा के आरोपों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई मांगों पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह आरोप लंबे समय से लगाया जाता रहा है कि क्वात्रोची के सोनिया गांधी (इतालवी मूल की) के साथ अच्छे संबंध थे और उसने भारत में अपने व्यापारिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया। क्वात्रोची की मृत्यु हो चुकी है। वर्ष 1987 में स्वीडिश सरकारी रेडियो द्वारा पहली बार रिश्वत से जुड़ी खबर दिए जाने के बाद बोफोर्स तोप सौदे में कथित रिश्वतखोरी की सीबीआई ने लंबे समय तक जांच की, जिसमें क्वात्रोची एक आरोपी था। भाटिया ने आरोप लगाया कि राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान रक्षा फाइलें क्वात्रोची के पास ले जाई जाती थीं, ताकि वह पसंद की कंपनियों के पक्ष में उनमें बदलाव कर सके। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व को जवाब देना चाहिए कि क्या यह राजीव गांधी द्वारा पद की शपथ का उल्लंघन नहीं था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि क्वात्रोची के बैंक खातों को सीबीआई ने 2005 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान सोनिया गांधी के इशारे पर 'डीफ्रीज' कर दिया था।

सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना ही बहुजनों के 'अच्छे दिन' लाने का एकमात्र विकल्प : मायावती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को दलित वर्ग के साथ-साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी पार्टी से जोड़ने का निर्देश देते हुए मंगलवार को कहा कि सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना ही बहुजनों के 'अच्छे दिन' लाने का एकमात्र विकल्प है।

मायावती ने यहां आयोजित बसपा के अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के पदाधिकारियों की राज्य-स्तरीय विशेष बैठक में कहा कि बहुजन समाज में से खासकर अन्य पिछड़े वर्गों के लोग भी हीन, जातिवादी और संकीर्ण राजनीति का जबरदस्त तौर पर शिकार हैं और आरक्षण के संवैधानिक लाभ से भी उसी प्रकार से वंचित हैं जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के नए-नए नियम-कानूनों में बांधकर दलितों के आरक्षण को लगभग निष्प्रभावी बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपमान से मुक्ति पाने के लिए 'बहुजन समाज' के सभी अंगों को आपसी भाईचारे के आधार पर संगठित करके और राजनीतिक शक्ति बनाकर सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाने के लिये नया पुरजोर अभियान शुरू किया जाए। उन्होंने कहा, गांव-गांव में लोगों को कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) के दलित तथा अन्य पिछड़े वर्ग विरोधी चाल, चरित्र और चेहरे के प्रति लोगों को जागरुक किया जाए। भाजपा, कांग्रेस, सपा आदि जातिवादी पार्टियों को परास्त करके राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना ही बहुजनों के सामने अपने अच्छे दिन लाने का एकमात्र बेहतर विकल्प है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बसपा ने हमेशा अलग-थलग और बिखरे रहे ओबीसी समाज के लोगों को मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू कराकर इन्हें पहली बार आरक्षण का संवैधानिक हक दिलाने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पार्टी और सरकार के स्तर पर जो काम किये हैं, उनसे देश में 'सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति' आंदोलन को नई शक्ति और मजबूती मिली थी। मायावती ने विरोधी पार्टियों पर एक साजिश के तहत एकजुट होकर बसपा को सत्ता से बाहर करने का आरोप लगाते हुए कहा, ''जातिवादी पार्टियों की भीतरी व खुली साजिशों के कारण बसपा के सन् 2012 में उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो जाने के बाद इन्हीं दलित व ओबीसी विरोधी ताकतों के सत्ता में आ जाने से इन वर्गों के हालात फिर से लगातार बदतर होते जा रहे हैं।

बैठक में मायावती ने अपने विभिन्न कार्यकालों में किये गये विकास कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ओबीसी वर्गों के उत्थान के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग करते हुए वर्ष 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था। इसका उद्देश्य यह था कि ओबीसी समाज को उनका संवैधानिक हक और योजनाओं का वाजिब फायदा मिल सके। मायावती ने कहा, ''जातियों के आधार पर बांटे, तोड़े व पछाड़े गये करोड़ों वंचित लोगों को बहुजन समाज की एकता में जोड़ने के बसपा के अभियान को नाकाम करने और खासकर चुनाव में उनके वोट की ताकत को बांटने की बुरी नीयत से बसपा विरोधी पार्टियों ने अनेक घिनौने हथकण्डे अपनाकर विभिन्न जातियों के छोटे-छोटे दल व संगठन बना दिये।''

लोकसभा ने वित्त विधेयक को 35 सरकारी संशोधनों के साथ मंजूरी दी

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा ने मंगलवार को वित्त विधेयक, 2025 को 35 सरकारी संशोधनों के साथ मंजूरी दी। इसमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर छह प्रतिशत डिजिटल कर को समाप्त करने का प्रावधान भी शामिल है। वित्त विधेयक, 2025 के पारित होने के साथ, लोकसभा ने बजटीय अनुमोदन प्रक्रिया का अपना कार्य पूरा कर लिया। उच्च सदन राज्यसभा अब इस विधेयक पर विचार करेगा। राज्यसभा से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद 2025-26 की बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये के व्यय की परिकल्पना की गई है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक है। अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल पूंजीगत व्यय 11.22 लाख करोड़ रुपये और प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ रुपये है। इसमें 42.70 लाख करोड़ रुपये का सकल कर राजस्व संग्रह और 14.01 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी का प्रस्ताव है।

मधुमिता शुक्ला हत्याकांड : अमरमणि त्रिपाठी की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश कारागार विभाग ने राज्य की 2018 की छूट नीति और इस तथ्य का हवाला देते हुए अमरमणि और मधुमणि की समयपूर्व रिहाई का आदेश जारी किया था कि दोनों ने अपनी सजा के 16 साल पूरे कर लिए हैं।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने मधुमिता की बहन निधि शुक्ला से कहा कि वह संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करें। पीठ ने पूछा, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया और उससे इस बाबत निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि कारागार विभाग ने दोषियों की उम्र और अच्छे आचरण को भी उनकी समयपूर्ण रिहाई का आधार बताया था, क्योंकि अमरमणि 66 साल और मधुमणि 61 वर्ष की थीं। मधुमिता की नौ मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय वह गर्भवती थीं और उनके अमरमणि के साथ कथित तौर पर प्रेम संबंध थे। सितंबर 2003 में अमरमणि को मधुमिता की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। देहरादून की एक अदालत ने अक्टूबर 2007 में अमरमणि और उनकी पत्नी को मधुमिता की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में नैनीताल उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत ने दंपति की सजा को बरकरार रखा था। मधुमिता हत्याकांड की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी।

न्यायमूर्ति वर्मा नकदी बरामदगी विवाद : राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेताओं की बैठक बुलाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले पर राज्यसभा के मुछ सदस्यों द्वारा चर्चा की मांग के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को घोषणा की कि वे इस मुद्दे पर मंगलवार को शाम साढ़े चार बजे विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक कर कुछ निर्णय करेंगे।

उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति धनखड़ ने बताया कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर नियम 267 के तहत, नियत कामकाज स्थगित कर चर्चा करने के लिए आठ नोटिस मिले हैं जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया है। इनमें एक नोटिस आईयूएमएल के हारिस बीरन का भी था। सभापति ने बताया कि उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की बैठक मंगलवार को शाम साढ़े चार बजे बुलाई है। धनखड़ ने बताया कि उन्होंने सोमवार को सदन के नेता जे पी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुलाकात की थी। उन्होंने कहा, यह मुद्दा निस्संदेह काफी गंभीर है। उनके अनुसार, खरगे ने सदन के नेताओं की बैठक बुलाने का सुझाव दिया था और नड्डा ने इस पर सहमति जताई थी।

उन्होंने कहा, ''हम तीनों ने घटनाक्रम पर गौर किया और यह भी देखा कि पहली बार, अभूतपूर्व तरीके से, भारत के प्रधान न्यायाधीश ने सब कुछ सार्वजनिक मंच पर डालने की पहल की।'' धनखड़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी मिलने से संबंधित फोटो, वीडियो सहित जांच रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की ओर परोक्ष रूप से इंगित कर रहे थे। दिल्ली के पॉश लुटियंस इलाके में 14 मार्च को न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के एक कमरे में आग लगने के बाद, उसे बुझाते समय अग्निशमन कर्मियों और पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से नकदी बरामद की थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आग की घटना के बाद नोटों की चार से पांच ''अधजली बोरियां'' जाए जाने की जांच के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है। सभापति धनखड़ ने कहा कि विधायिका और न्यायपालिका तब बेहतर तरीके से काम करती हैं, जब वे अपने-अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने पास उपलब्ध संपूर्ण सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में डाले जाने की को देश भर में सराहना की गई है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऐसा होते हुए दिखना भी चाहिए और इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

अगस्ता वेस्टलैंड : अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में संशोधन की अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा, जिसमें उसने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में जमानत देते समय उस पर लगाई गई कुछ शर्तों में संशोधन करने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने मिशेल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। इस याचिका में मिशेल ने पांच लाख रुपये की जमानत राशि जमा कराने की शर्त को हटाने का अनुरोध किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध की है। धनशोधन मामले में मिशेल को जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने चार मार्च को उसे पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने के अलावा निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था। आरोपी ने कहा कि भारत द्वारा जमानत राशि प्रस्तुत करने की शर्त को संशोधित किया जा सकता है या माफ किया जा सकता है, क्योंकि वह एक विदेशी नागरिक है और यहां उसका कोई ज्ञात रिश्तेदार नहीं है या देश में उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। याचिका में मिशेल ने पासपोर्ट जमा करने की शर्त को हटाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उसका पुराना पासपोर्ट समाप्त हो चुका है और नया पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया में कम से कम चार से आठ सप्ताह का समय लग सकता है। मिशेल को संबंधित सीबीआई मामले में 18 फरवरी को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गई थी। मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे सीबीआई तथा ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

सुविचार

जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में कह नहीं सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

कई समस्याओं का एक समाधान

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया जिस तरह युवाओं में साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं, उसे और बड़े स्तर पर ले जाने की जरूरत है। इससे व्यक्ति, परिवार, समाज और देश, सबको अनेक फायदे होंगे। जब केंद्रीय मंत्री साइकिल सवारों का नेतृत्व करते हुए युवाओं को इसके फायदे बताएंगे तो निश्चित रूप से यह संदेश दूर तक जाएगा। हालांकि रास्ते में कई मुश्किलें भी हैं। हमारी कितनी सड़कें ऐसी हैं, जो साइकिल सवारों के लिए सुरक्षित मानी जा सकती हैं? देश में ऐसी परिवहन नीति होनी चाहिए, जिसमें साइकिल सवारों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। साथ ही, ऐसे लोगों के प्रति सम्मान की भावना पैदा होनी चाहिए। जो व्यक्ति साइकिल चलाता है, वह कहीं-न-कहीं देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को फायदा ही पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मन की बात' कार्यक्रम में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बढ़ता मोटापा देश के लिए एक चुनौती है। अगर लोग साइकिल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो इस चुनौती का दृढ़ता से सामना किया जा सकता है। साइकिल चलाने से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं नियंत्रण में रहती हैं। पेट्रोल, भारी मेंटेनेंस और पार्किंग के खर्चों से मुक्ति मिलती है सो अलग। आज कई देश साइकिल को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना चुके हैं। नीदरलैंड ने हजारों किमी की साइकिल लेन बनाकर अपने नागरिकों को बड़ा उपहार दिया है। वहां किसी साइकिल सवार को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि पीछे से कोई ट्रक या कार आकर टक्कर मार देगी! साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए उस निवेश ने नागरिकों को कई तरह से फायदा पहुंचाया है।

एम्स्टर्डम जैसे शहर में कई कंपनियों के उच्चाधिकारी साइकिल से दफ्तर जाते हैं। यहां बात सिर्फ अच्छी सड़कों और सुविधाओं की नहीं है, मानसिकता की भी है। नीदरलैंड में साइकिल चलाने को किसी व्यक्ति की आर्थिक या सामाजिक स्थिति से जोड़कर नहीं देखा जाता।

एम्स्टर्डम जैसे शहर में कई कंपनियों के उच्चाधिकारी साइकिल से दफ्तर जाते हैं। यहां बात सिर्फ अच्छी सड़कों और सुविधाओं की नहीं है, मानसिकता की भी है। नीदरलैंड में साइकिल चलाने को किसी व्यक्ति की आर्थिक या सामाजिक स्थिति से जोड़कर नहीं देखा जाता। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि नीदरलैंड में साइकिल को बढ़ावा देने से वायु प्रदूषण में काफी कमी आई है। इससे ट्रैफिक उत्सर्जन कम हुआ है। यही नहीं, जिन लोगों की फिटनेस अच्छी हुई, उनके स्वास्थ्य खर्चों में कमी आई। जिन रास्तों पर साइकिल से आवागमन बढ़ा, वहां ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं लगभग खत्म हो गईं। इससे समय और ईंधन की बचत हुई। इसी तरह डेनमार्क एक अच्छा उदाहरण है, जहां सरकार साइकिल खरीदने पर टैक्स में छूट समेत कई तरह की रियायतें देती है। कोपेनहेगन को तो साइकिलिंग कैपिटल कहा जाता है। क्या हम दिल्ली में ऐसी व्यवस्था लागू कर सकते हैं? क्या महानगरों में रहने वाला साधन-संपन्न वर्ग हफ्ते में दो दिन कारों का इस्तेमाल बंद या सीमित करने के लिए तैयार होगा? क्या वह साइकिल को बढ़ावा देने के लिए आगे आएगा? जब तक समर्थ एवं संपन्न लोग, वरिष्ठ नेता, अधिकारी आदि साइकिल पर सवारी नहीं करेंगे, समाज में बदलाव कैसे आएगा? जर्मनी ने अपने यहां साइकिल हाईवे बना दिए हैं। जब सरकार ने साइकिल सवारों को प्रोत्साहन देना शुरू किया तो घरेलू रोजगार भी बढ़ा। वहां युवा नए-नए प्रयोग कर साइकिलों के आकर्षक मॉडल पेश कर रहे हैं। पिछले दिनों भारत में सोशल मीडिया पर कुछ युवाओं की कहानी चर्चा में रही थी, जिन्होंने बांस का इस्तेमाल कर साइकिल बना दी! चूंकि भारत में बांस खूब उगाया जाता है। अगर ऐसी साइकिलों का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाए तो हमारे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। इसके लिए सरकार को इच्छाशक्ति दिखानी होगी। वहीं, लोगों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। साइकिल ऐसा सुंदर आविष्कार है, जिसमें कई बीमारियों और पर्यावरणीय एवं आर्थिक समस्याओं को दूर करने की भरपूर शक्ति तथा सामर्थ्य है।

ट्वीटर टॉक

पिछले दिनों देश के गौरव और अजेय योद्धा महाराणा सांगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी घोर निंदनीय है। यह आसमान की ओर कीचड़ उछालने जैसा है। आज हर देशभक्त महाराणा सांगा के बारे में की गई ग़लत और झूठी टिप्पणी से आहत है।

-वसुंधरा राजे

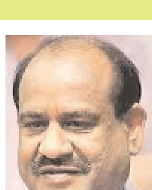

महिला कबड्डी विश्व कप-2025 के फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर विश्व विजेता बनने पर भारतीय महिला टीम को बहुत - बहुत बधाई। करोड़ों देशवासी इस विजय से गौरवान्वित हैं, आपकी उपलब्धि पर हर्षित हैं।

-ओम बिरला

बालोतरा जिले में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग-25 के पचपदरा बागुंडी खंड का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य की धीमी गति को लेकर ठेकेदार, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता एनएच वृत जोधपुर को नोटिस देने के आदेश दिए।

-दीया कुमारी

प्रेरक प्रसंग

अकेलेपन की संगति

योगी मुक्तानंद का एक शिष्य अकेलेपन के भय से कोई काम नहीं करता था। अकेलापन उसमें किसी अनजाने भय को भर देता था। एक दिन योगी जी ने उपदेश दिया, अगर आपको सही राह चलना है तो अकेलेपन के भय से मुक्त होना होगा। अकेलेपन से कैसा डर। भीड़ में हमेशा अपने मन का कुछ नहीं होता, यह तो मानना ही होगा। संगति का भी अपना रस है और अपनी संगति का भी अपना ही एक अनोखा रस है। इतना भी तो सोचकर देखो कि संगति केवल मनुष्य की ही नहीं होती। इतनी मनमोहक और खरी-खरी कुदरत है, सच कहती किताबें हैं। यह क्या कम बेहतरीन संगी-साथी हैं। इनसे लगाव रखने वाला कभी धोखे में नहीं रहता है।

सामयिक

संघ के 'कर्नाटक मंथन' में नए संकल्प, नई दिशाएं

ललित गर्ग
मोबाइल : 9811051133

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक अपने स्थापना के शताब्दी वर्ष प्रवेश के पावन एवं ऐतिहासिक अवसर पर बेंगलूरु में सफलतापूर्णक एवं ऊर्जामय माहौल में संपन्न हुई, जिसमें औरंगजेब विवाद, तीन-भाषा फॉर्मूला, परिसीमन और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा ने एक अपूर्व वातावरण का निर्माण किया। जिसमें दुनिया में शांति और समृद्धि लाने के तर्क पर एक सौहार्दपूर्ण और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का आह्वान किया गया। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा महासचिव बीएल संतोष सहित आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। आरएसएस की स्थापना विशेष रूप से भारतीय हिन्दू समाज में राष्ट्रीयत्व भाव जागृत करने, हिन्दुओं को संगठित करने एवं हिन्दू समाज के बीच समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से हुई और इन सौ वर्षो में न केवल इन लक्ष्यों को हासिल किया गया है बल्कि अनेक रचनात्मक एवं सृजनात्मक गतिविधियों एवं योजनाओं के साथ अपनी एक स्वतंत्र एवं अलग छवि का निर्माण किया है। इस वर्ष की वार्षिक बैठक न केवल विशेष बल्कि नवीन संकल्पों की वाहक बनी है, क्योंकि बैठक ने सकारात्मक क्रांतिकारी विचारों से न केवल राष्ट्र में सक्रिय नकारात्मक एवं अराष्ट्रीय ताकतों को सख्त संदेश दिया गया बल्कि पड़ौसी बांग्लादेश-पाकिस्तान-चीन आदि देशों की कुचेष्टाओं के लिए ललकारा भी गया एवं सावधान भी किया गया है। अठहत्तर वर्ष की देहरी पर खड़े होकर राष्ट्र के अतीत को देखा-परखा जाए तो ऐसा लगता है कि अब राष्ट्र का कायाकल्प हो रहा है। मूलभूत आस्थाओं एवं राष्ट्रीयता के दृढ़ीकरण के साथ देश में जो नई चेतना आई है, वह संघ जैसे शक्तिशाली संगठन का जीवंत साक्ष्य है। राष्ट्रीयता, स्व-पहचान, स्वदेशी-भावना, हिन्दू-संस्कृति के ऊर्जा के अक्षय स्रोतों की खोज में जो प्रयत्न किया जा रहा है, वह अभूतपूर्व है। जन-आकांक्षा के अनुरूप राष्ट्र को जिस युगीन परिवेश में प्रस्तुति दी जा रही है, वह असाधारण है। इन सब परिवर्तनों-परिवर्धनों एवं राष्ट्र को सशक्त करने के बावजूद संघ की सादगी का सौन्दर्य निराला है और कर्नाटक बैठक इसी सादगी के सौन्दर्य के अनूठेपन को लिये हुई थी।

दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन ने अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सभी स्वयंसेवकों से आग्रह किया कि वे पूरे समाज को सज्जन शक्ति के नेतृत्व में एकजुट कर, दुनिया के सामने एक संगठित और सामंजस्यपूर्ण भारत का आदर्श प्रस्तुत करें। इसमें बैठक में मुख्य रूप से कहा गया है कि भारत एक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति वाला देश है और इसमें एकजुट दुनिया बनाने का अद्भुत ज्ञान एवं सक्षमता है। आरएसएस ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य पूरी मानवता को विभाजन और विनाश की प्रवृत्तियों से बचाना है और सभी जीवों के बीच शांति और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, आरएसएस ने हिंदू समाज को अपने वैश्विक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए संगठित और सामूहिक जीवन की आवश्यकता पर बल दिया है, जो 'धर्म' पर आधारित आत्मविश्वास से भरा हो। साथ ही बैठक में पारित प्रस्तावों में यह भी कहा गया कि सभी प्रकार के भेदभावों को खारिज कर, एकजुट आचरण और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाते हुए हमें एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए। यह समाज भौतिक समृद्धि के साथ-साथ आध्यात्मिकता से भी परिपूर्ण होगा, जो समाज की समस्याओं का समाधान करेगा और चुनौतियों को कम करेगा। इस वर्ष की बैठक का हर बोल अनमोल है, हर चरण एक मंजिल है, हर संकल्प नये भारत-सशक्त भारत की दिशा है और हर क्रिया एक सन्देश है। संघ का जीवन और दर्शन, विचार और सोच अन्तरमन को कुरेदने वाली ऐसी प्रेरणा है जो जागृत अवस्था में सोने वाले लोगों का झकझोर देती है।

इस बैठक की खास बात यह रही है कि इसमें संघ की तरफ से भाजपा के बारे में सीधे सवालों से दूरी बनाए रखी गयी। हालांकि, परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण के राज्यों में सीटें कम नहीं होने को लेकर भाजपा को संदेश भी दे दिया। परिसीमन को लेकर संघ ने साफ कहा कि दक्षिणी राज्यों का लोकसभा में अनुपात वही रहेगा। इसके साथ ही

संघ ने तीन-भाषा फार्मूले पर संतुलित रुख बनाए रखा गया। ऐसे समय में जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार त्रिभाषा फार्मूले को लेकर असमंजस में हैं, आरएसएस ने इस विवाद को दरकिनार करते हुए मातृभाषा, व्यक्ति के निवास स्थान की क्षेत्रीय भाषा तथा करियर की भाषा, जो अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा हो सकती है, के उपयोग की वकालत की है। संघ ने महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद को लेकर मुगल शासक की तीव्र एवं तीखी आलोचना की। खास बात यह देखने को मिली कि संघ की तरफ से औरंगजेब की आलोचना के साथ ही उसके भाई दारा शिकोह का जश्न भी मनाया, क्योंकि दारा शिकोह सामाजिक सद्भाव में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत के मूल्यों के खिलाफ जाने वाले लोगों को आदर्श बनाया गया था। औरंगजेब भारत के 'लोकाचार' के खिलाफ था और अगर वैसी ही 'आक्रमणकारी मानसिकता' अभी भी मौजूद है तो यह देश के लिए खतरा है। जो इस भूमि की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की कुचेष्ठा भी है। निश्चित ही इस तरह कोई विकृत संस्करण या नैरेटिव प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसका मुकाबला किया ही जाना चाहिए।

कर्नाटक बैठक की टंकार में संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। बांग्लादेश के हिन्दू समाज के साथ एकजुटता से खड़े होने का 'आह्वान' शीर्षक वाले एक प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय ताकतों और अमेरिका में 'डीप स्टेट' के प्रयासों का उल्लेख किया गया। संघ ने स्पष्ट किया कि 'बांग्लादेश में हिंदुओं की जिम्मेदारी भारत की है और हम इस कर्तव्य से बच नहीं सकते।' निश्चित ही धार्मिक संस्थानों पर व्यवस्थित हमलों, क्रूर हत्याओं, जबरन धर्मांतरण और हिन्दुओं की संपत्तियों को नष्ट करने के चक्र ने बांग्लादेश में हिन्दू समुदाय के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है। इसलिए संघ द्वारा धार्मिक असहिष्णुता और मानवाधिकारों के उल्लंघन के इन कृत्यों की कड़ी निंदा की गई है और वैश्विक समुदाय से निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। इस बैठक ने हिन्दुओं को आश्वस्त किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के भविष्य में कोई मुश्किल स्थिति आती है, तो हम पीछे नहीं हट सकते। अगर ऐसी स्थिति आती है, तो हम उसका समाधान करेंगे। भाजपा के नये अध्यक्ष के चयन को लेकर भी संघ ने स्पष्ट किया कि भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर उसका पार्टी के साथ कोई मतभेद नहीं है। संघ ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से भाजपा पर निर्भर है। भाजपा की प्रक्रिया चल रही है, सदस्यता पूरी हो चुकी है और विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन हो चुका है। आने वाले दिनों में भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इससे पहले चर्चा चल थी कि भाजपा और आरएसएस किसी उपयुक्त उम्मीदवार पर सहमत नहीं हो पाए हैं, जिससे दोनों संगठनों के बीच टकराव की अटकलें लगाई जा रही हैं।

कर्नाटक बैठक से एक बार फिर पुरजोर तरीके से उजागर हुआ कि संघ हिन्दू सनातन संस्कृति को भारत के जन-जन के मानस में प्रवाहित करने का सफल एवं सार्थक कार्य करने को प्रतिबद्ध है। ताकि प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो एवं उनके लिये भारत प्रथम प्राथमिकता बन सके। यह कार्य संघ अपने स्वयंसेवकों द्वारा समाज के बीच जाकर करने का प्रयास करता है और यह कार्य आज पूरे विश्व में शांति एवं समरसतापूर्ण जीवन स्थापित करने के लिये एक जरूरी आवश्यकता है। पिछले आठ दशकों में लगातार हिन्दू-संस्कृति को कमजोर करने की राजनीतिक चालों को भी संघ ने समय-समय पर आड़े हाथ लिया है। दरअसल हिन्दू धर्म नहीं, विचार है, संस्कृति है। हिन्दू राष्ट्र होने का अर्थ धर्म से न होकर हिन्दू संस्कृति के सर्वग्राही भाव से है। हिन्दू संस्कृति उदारता का अन्तर्निहित शंखनाद है क्योंकि पूरे विश्व में यह अकेली संस्कृति है जो बहुविचारवाद यानी सभी धर्म, विचार एवं संस्कृतियों को स्वयं में समेटे हैं। कर्नाटक बैठक हिन्दू संस्कृति के वृहद स्वरूप का ही सौपान बनी है।

नजरिया

बिहार में इफ्तार पार्टी में पार्टियों द्वारा अपनी ताकत का प्रदर्शन

अशोक भाटिया
मोबाइल : 9221232130

बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जाने लगी है। चुनावी माहौल के बीच रमजान का महीना चल रहा है, जिसके चलते रोजा इफ्तार दावत की बहार देखने को मिल रही। सियासी पार्टियां रोजा इफ्तार के बहाने मुस्लिम समुदाय वोटबैंक को साधने की है, जिसके लिए नमाज पढ़ने वाली टोपी लगाने से लेकर गमछे को पहनने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस तरह मुस्लिम रंग में रचे-बसे हुए नेता नजर आ रहे हैं, किसी की दावत में जाने से मुस्लिम तंजी में इनकार कर रही तो किसी की महफिल में जाने को बेकरार हैं। इस तरह बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स होती दिख रही है?

मंगलवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। लालू प्रसाद के इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों के लोग और वामपंथी दल और कांग्रेस के कुछ विधायक शामिल हुए। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई। यही नहीं वीआईपी के मुकेश भी नहीं पहुंचे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कह चुके है कि अबकी चुनाव में उन्हें बड़ा हिस्सा नहीं मिला तो वो अकेले चुनाव लड़ेगी। ज्ञात हो कि रमजान के महीने में हर साल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। लालू प्रसाद हर साल अपने सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे। लेकिन आज लालू प्रसाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास 12 स्ट्रेंड रोड पर किया गया। इफ्तार पार्टी में लालू प्रसाद यादव खुद एक्टिव दिखे। इफ्तार पार्टी में लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी सहित राजद के सभी विधायक महागठबंधन के सहयोगी वामपंथी दलों के नेता और कई विधायक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुई।

बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय के अनुसार बिहार में महागठबंधन की सियासत लालू प्रसाद यादव के इर्द-गिर्द घूमती रहती थी। बिहार में कांग्रेस की राजनीति भी पिछले 25 वर्षो से राजद के सहारे ही चलती रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब अपना संगठन विस्तार करने में लगी हुई है। यही कारण है कि नए प्रभारी एवं नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है।लालू प्रसाद के द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं की दूरी यह दिखा रही है कि महागठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। कांग्रेस के कुछ एक विधायकों का पहुंचना और बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं का इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होना यह संकेत दे रहा है कि कहीं कांग्रेस कुछ अलग राजनीति या रणनीति तो नहीं बना रही। सबसे बड़ी बात है कि कृष्णा

अल्लावारु जब से बिहार के प्रभारी बने हैं एक बार भी लालू प्रसाद से मुलाकात करने नहीं गए।

लालू प्रसाद द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में महागठबंधन में नए राजनीतिक समीकरण भी देखने को मिला। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, बिहार अध्यक्ष प्रिंस राज और पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरजभान सिंह इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में पशुपति कुमार पारस ने बताया कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। बिहार में नई राजनीतिक समीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि ''समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में कई मुस्लिम नेताओं के साथ समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि इससे पहले कई मुस्लिम संगठनों की ओर से इफ्तार पार्टी में जाने से इनकार किया गया था। जदयू के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार मुस्लिम के साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बॉयकॉट के बावजूद बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन भी सीएम आवास पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ने ही मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया।

नीतीश कुमार ने जदयू के मुस्लिम नेताओं को पैचअप में लगाया है, लेकिन उसके बावजूद इफ्तार पार्टी पर असर इस बार दिखा है। हालांकि पार्टी में कैमरा और मोबाइल दोनों ले जाने की मनाही थी। इफ्तार पार्टी में जिन लोगों को मुख्यमंत्री आवास में एंट्री हुई उन्हें मोबाइल भी बाहर रखना पड़ा और कड़ी जांच के बाद जाने दिया गया है पास के माध्यम से ही एंट्री था। जदयू मुस्लिम नेताओं ने कहा यह राजद की साजिश है। चुनावी साल में लेकिन इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने मुसलमान के लिए जितना काम किया है। मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ हैं। मुख्यमंत्री आवास में हुए कर पार्टी में एनडीए के कई नेता भी शामिल हुए।ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए-शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात-ए-इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी ने वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार और जदयू के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इफ्तार पार्टी बायकाट किया था।

बताया जाता है कि वक्फ बिल को लेकर जदयू ने लोकसभा में पुरजोर समर्थन किया था। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने समर्थन करते हुए इसे मुसलमान के हित में बताया था। उसके बाद से हैं मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार से अपनी नाराजगी जताते रहे हैं नीतीश कुमार के साथ बैठक कर भी अपनी नाराजगी जताई है। बताया जाता है कि बिहार में सीमांचल सहित तीन दर्जन से अधिक सीट ऐसे हैं। जिसमें मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं 243 सीटों में से तीन दर्जन सीटों में मुस्लिम वोटरों की आबादी 20 से 40 प्रतिशत के करीब है 11 सीट तो ऐसे हैं जहां 40 फीसदी से भी अधिक वोट मुस्लिम के हैं।मुस्लिम वोटरों पर राजद और महागठबंधन की नजर तो है ही साथ ही एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की भी नजर है। सीमांचल में 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। मुस्लिम पहले से नीतीश कुमार से नाराज हैं और वक्फ बिल को लेकर उनकी नाराजगी और बढ़ी है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों के बायकाट ने नीतीश कुमार की मुश्किलें और बढ़ा दी है।

सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार के अध्यक्ष इर्शादुल्लाह के अनुसार ये सियासी स्टंट है। ये आरजेडी वालों का क्रिएट किया गया है। इफ्तार का कभी ठुकराया नहीं जाता है। ये पहली बार देख रहा हूं कि इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया गया है। यह दुखद है। चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 50 फीसदी नीतीश को वोट करने जा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है। इफ्तार के बहाने बिहार में सियासी उठा पटक भी होता रहा है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17 प्रतिशत के करीब है। आरजेडी इतनी बड़ी आबादी को अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों और यादवों का एम-वाई समीकरण बना लिया है। यादवों की 14 प्रतिशत जनसंख्या मिला कर यह आबादी 31-32 प्रतिशत के करीब हो जाती है। मुसलमान भाजपा को तो वोट करते ही नहीं। अब जेडीयू से भी कट गए। ऐसे में थोक में मुसलमानों के वोट पर महागठबंधन की नजर है। आरजेडी कैंप यकीनन इस बात पर खुशी होगी कि उलेमाओं ने नीतीश की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। पर, यह भी सच है कि मुस्लिम वोटों का दावेदार तब अकेले महागठबंधन की ही पार्टियां नहीं होंगी।

बिहार के उलेमाओं ने जब सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया। इसकी उलेमाओं ने शर्त भी रखी। स्पष्ट कहा कि एनडीए में रहते हुए वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें, वर्ना वे इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करेंगे। नीतीश कुमार बिना कोई प्रतिक्रिया दिए खामोश रह गए। बायकॉट के पत्र पर दस्तखत करने वाले रविवार को आयोजित पार्टी में नहीं पहुंचे। इसके बावजूद खासा तादाद में रोजेदारों और सियासी जमावड़े के बीच इफ्तार पार्टी संपन्न हुई। नीतीश ने इफ्तार के जरिए अपने 225 वाले लक्ष्य को फिक्स कर लिया है। यह सच भी है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में मुसलमानों के हित में काफी काम हुए हैं। इसके बावजूद मुसलमानों के वोट जेडीयू को उस तरह नहीं मिलते, जितना उन्होंने उनके लिए काम किए हैं। इसका कारण शायद नीतीश कुमार का एनडीए में होना है। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो जेडीयू के टिकट पर खड़े उम्मीदवारों में एक भी नहीं जीत पाया। जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। भला हो जमा खान का, जो जीते तो चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर, लेकिन सदन पहुंचते ही उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया और नीतीश मंत्रिमंडल में उनके भरोसे के साथी बन गए।

ज्यादा दिन नहीं बीते, जब जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा था कि मुगालते में न रहें, मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करते। यह बात अलग-अलग मौकों पर उन्होंने दो बार कहीं थी । उनसे पहले जेडीयू के ही एक सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी ऐसी ही बात कही थी। उन्होंने तो ललन सिंह से भी एक कदम आगे बढ़ कर कह दिया था कि उनको मुसलमानों और यादवों ने वोट नहीं दिया। इसलिए वे उनका कोई काम नहीं करेंगे। उलेमाओं के बायकॉट के ऐलान के बाद नीतीश कुमार की चुप्पी से अंदाज लगता है कि उन्हें भी इससे पीड़ा पहुंची है। पहुंचे भी क्यों नहीं, नीतीश कुमार ने न सिर्फ उनके लिए काम किए, बल्कि उन पर किसी तरह का जुल्म भी अपने कार्यकाल में नहीं होने दिया है। उधर जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर की भी मुस्लिम वोटों पर चौकस नजर है। उन्होंने 40 मुसलमानों को इस बार विधानसभा का टिकट देने की घोषणा की है। एआईएमआईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम वोटों के हिस्सेदार बनेंगे ही। मुस्लिम बहुल सीमांचल की पांच सीटें पिछली बार जीत कर और गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को हरा कर वे अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। इसलिए महागठबंधन को अभी इतराने से परहेज करना ही श्रेयस्कर होगा।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

घरेलू शेयर बाजारों में लगातार सातवें सत्र में तेजी, सेंसेक्स 33 अंक चढ़ा

मुंबई/भाषा। स्थानीय शेयर बाजार में मुनाफावसूली हावी रहने से मंगलवार को मानक सूचकांक मामूली बढ़त के साथ लगातार सातवें दिन चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स 33 अंक की बढ़त में रहा जबकि निफ्टी में 10 अंक का सुधार देखा गया।

विश्लेषकों ने कहा कि एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी दिग्गज कंपनियों में लिवाली जारी रहने के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपये में आई गिरावट से बाजार का लाभ सीमित रहा। बीएसई का 30 शेयर वाला सूचकांक सेंसेक्स 32.81 अंक यानी 0.04% बढ़कर 78,017.19 अंक पर बंद हुआ। एक समय यह 757.31 अंक बढ़कर 78,741.69 अंक तक पहुंच गया था लेकिन मुनाफावसूली ने इसकी बढ़त सीमित कर दी। एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी 10.30 अंक यानी 0.04% बढ़कर 23,668.65 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों में से अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर में बढ़त दर्ज की गई।

भारत और सिंगापुर ने 'ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर' के लिए मिलाया हाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सिंगापुर/भाषा। सिंगापुर और भारत ने ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर (जीडीएससी) के लिए मंगलवार को एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डिजिटलीकरण और कार्बन मुक्त परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सिंगापुर के समुद्री एवं बंदरगाह प्राधिकरण और बंदरगाह, पोत परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार, सिंगापुर-भारत जीडीएससी से दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा तथा शून्य या लगभग शून्य जीएचजी उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों के विकास, इस्तेमाल तथा डिजिटल समाधानों को अपनाने में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि समुद्री क्षेत्र के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी सिंगापुर यात्रा से दीर्घकालिक संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी'' दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा और व्यापक बनाएगी।

सोनोवाल सिंगापुर की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। वह समुद्री सप्ताह में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें दुनिया भर से 20,000 प्रतिनिधियों और प्रदर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। आशय पत्र के तहत, दोनों पक्ष समुद्री डिजिटलीकरण और कार्बन मुक्त परियोजनाओं पर सहयोग करेंगे। इसमें उन प्रासंगिक हितधारकों की पहचान करना शामिल है जो इस प्रयास में योगदान दे सकते हैं। साथ ही सिंगापुर-भारत जीडीएससी पर समझौता ज्ञापन के जरिये साझेदारी को औपचारिक रूप देने की दिशा में काम करेंगे।

आशय पत्र पर जल एवं जलमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव आर. लक्ष्मणन और सिंगापुर समुद्री एवं बंदरगाह प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी तेओ इंग दिन्ह ने हस्ताक्षर किए।

सिंगापुर के वरिष्ठ स्थायित्व एवं पर्यावरण राज्य मंत्री एमी खोर तथा पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यहां आशय पत्र पर हस्ताक्षर के समय उपस्थित रहे। समुद्री सप्ताह 24 से 28 मार्च 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया कि ''भारत सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी है, जिसमें हरित समुद्री ईंधन का प्रमुख उत्पादक तथा निर्यातक बनने की क्षमता है''...साथ ही प्रमुख ट्रांस-शिपमेंट' और बंकरिंग' केंद्र के रूप में सिंगापुर एक गतिशील अनुसंधान व नवाचार परिवेश का समर्थन करता है।

न्यूयॉर्क में भारत के वाणिज्य दूतावास में 'बिहार दिवस' मनाया गया

न्यूयॉर्क/भाषा। न्यूयॉर्क में 'बिहार दिवस' मनाने के लिए शनिवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बिहार की संस्कृति एवं विरासत को सराहा गया और राज्य से संबंध रखने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय के चार विशिष्ट सदस्यों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

'बिहार फाउंडेशन यूएसए' (ईस्ट कोस्ट) ने बताया कि यह आयोजन उसके, भारतीय वाणिज्यदूतावास और 'बिहार-झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका' (बीजेएएनए) के सहयोग से किया गया। इसमें भारतीय-अमेरिकी समुदाय के 130 से अधिक सदस्य शामिल हुए जिन्होंने बिहार की संस्कृति, उसके द्वारा की गई प्रगति और दुनियाभर में उसकी बढ़ती मौजूदगी को सराहा। इस अवसर पर महेश कुमार (टाइगर एनालिटिक्स' के संस्थापक), डॉ. अभिषेक तिवारी ('केपीएमजी' कंपनी के ग्लोबल हेड ऑफ पीपल'), शरद कुमार (बैंक ऑफ अमेरिका' के प्रबंध निदेशक) और कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रकाश झा को बिहार विश्व गौरव सम्मान' दिया गया। इन सभी को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), वित्त, कृषि और नेतृत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दौरान शुभकामना संदेश दिए।

'बिहार फाउंडेशन' के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महेश कुमार की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पटना में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रवासी भारतीयों को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए तथा अपनी भूमि के लिए काम करना चाहिए। न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्यदूत बिनय प्रधान ने बिहार के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए नालंदा विश्वविद्यालय, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और महान गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री आर्यभट्ट का उल्लेख किया।

'बिहार फाउंडेशन पटना' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुंदन कुमार ने बिहार से संबंध रखने वाले प्रवासी समुदाय की भलाई के लिए संगठन की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रवासी भारतीय शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना की घोषणा की। इस मौके पर बिहार की प्रसिद्ध लोकगायिका एवं पद्म विभूषण से सम्मानित दिवंगत शारदा सिन्हा का एक वीडियो प्रसारित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यह वीडियो उनके बच्चों ने तैयार किया था।

टिकाऊ विमान ईंधन भारत के लिए एक अवसर: एयरबस सीईओ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

टूलूज (फ्रांस)/भाषा। एयरबस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गियौम फाउरी ने कहा है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने वाला टिकाऊ विमानन ईंधन (एसएएफ) भारत के लिए एक अवसर बन सकता है।

एयरबस को भारत में बहुत अधिक संभावनाएं दिखाई देती हैं, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल है। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए भारत का मतलब ''वृद्धि'' है। भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने एयरबस को सैकड़ों विमानों के ऑर्डर दिए हैं। कंपनी के पास भारत में सी295 विमान के लिए संयुक्त उद्यम में फाइनल असेंबली लाइन' (एफएलए) है और इस साल हेलीकॉप्टर एच125 के लिए एक एफएएल स्थापित किया जाएगा। फाउरी ने सोमवार को कहा, एसएएफ भारत के लिए एक अवसर है... टिकाऊ ईंधन भारत के एजेंडा में सबसे ऊपर है... भारत में वैश्विक विमानन कारोबार का बड़ा हिस्सा है। इसलिए भारत की वैश्विक व्यवस्था में बड़ी भूमिका और बड़ी जिम्मेदारी है। वह टूलूज में एयरबस शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान पीटीआई-भाषा से बात कर रहे थे। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में विमानन क्षेत्र की करीब 2-3% हिस्सेदारी है। एसएएफ इस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। उन्होंने टिकाऊ ईंधन के इस्तेमाल को विमानन क्षेत्र में बड़ी क्रांति बताया और कहा इस लक्ष्य को अभी हासिल किया जाना है।

शांतिसैनिकों के खिलाफ अपराध करने वालों को न्याय के कठघरे में लाया जाए : सुरक्षा परिषद में भारत

संयुक्त राष्ट्र/भाषा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में कहा कि शांति स्थापना का कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और इसमें शांतिसैनिकों को गैर-सरकारी तत्वों, सशस्त्र समूहों तथा आतंकवादियों से जूझना पड़ता है। भारत ने यह भी कहा कि जटिल संघर्षों और खतरों के इस युग में शांति स्थापना के खिलाफ अपराध करने वालों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।

ये टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अनुकूलता को बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस के दौरान कीं। उन्होंने कहा, ''आज संयुक्त राष्ट्र शांतिसैनिकों को गैर-सरकारी तत्वों, सशस्त्र समूहों, आतंकवादियों और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्कों की मौजूदगी से जूझना पड़ रहा है। प्रौद्योगिकी प्रगति ने गलत/अभद्र/भ्रामक सूचना और घृणास्पद भाषण, ड्रोन, आईईडी आदि सहित नये युग के हथियारों के रूप में नई चुनौतियां पैदा की हैं। ये कुछ नई वास्तविकताएं हैं, जिनका शांतिसैनिकों को सामना करना पड़ रहा है।''

राजदूत ने कहा, ''शांतिसैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। जटिल संघर्षों और विषम खतरों से भरे इस युग में, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शांति के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वालों को पर्याप्त सुरक्षा मिले और शांतिसैनिकों के खिलाफ अपराध करने वालों को न्याय के कठघरे में लाया जाए।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैन्य/पुलिस योगदान देने वाले देशों को शत्रुतापूर्ण वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हरीश ने कहा, भारत अपने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (सीयूएनपीके) में आधुनिक शांति स्थापना की विशिष्ट मांगों का समाधान करने वाले पाठ्यक्रमों को तैयार करने और पेश करने का इच्छुक है, जो दो दशकों से अधिक समय से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांतिसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। इस बात पर जोर देते हुए कि उन्नत निगरानी, संचार और डेटा विश्लेषण उपकरणों के उपयोग को शांति अभियानों में एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि स्थितिजन्य जागरूकता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार हो सके, हरीश ने कहा कि भारत इस संबंध में प्रौद्योगिकी सक्षमकर्ता के रूप में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि शांति स्थापना के लिए आधुनिक चुनौतियों का मुकाबला करने के वास्ते शांति स्थापना मिशन को पर्याप्त रूप से वित्त और संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

जापान की अदालत ने 'यूनिफिकेशन चर्च' भंग करने का आदेश दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तोक्यो/एपी। जापान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 2022 में हुई हत्या के मामले की जांच के दौरान किए गए सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 'यूनिफिकेशन चर्च' को भंग करने का आदेश दे दिया।

'तोक्यो जिला अदालत' द्वारा 'यूनिफिकेशन चर्च' के कानूनी दर्जे को रद्द किए जाने का मतलब है कि वह कर से छूट का अपना विशेषाधिकार खो देगा और उसे अपनी संपत्तियां बेचनी होंगी। हालांकि 'यूनिफिकेशन चर्च' इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील कर सकता है। यह आदेश दक्षिण कोरिया स्थित इस प्रभावशाली संप्रदाय को भंग करने के जापान के शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध के बाद दिया गया है। मंत्रालय ने यह अनुरोध करते समय संप्रदाय द्वारा हेरफेर करके धन एकत्र किए जाने और भर्ती रणनीतियां अपनाए जाने का हवाला दिया था। इन रणनीतियों से इसके अनुयायियों में भय पैदा हुआ और उनके परिवारों को नुकसान पहुंचा। 'यूनिफिकेशन चर्च' की जापानी शाखा ने इस अनुरोध की आलोचना करते हुए इसे अपने अनुयायियों की धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए गंभीर खतरा बताया था। आबे की 2022 में हुई हत्या की जांच के दौरान 'यूनिफिकेशन चर्च' और जापान की सत्तारूढ़ 'लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी' के बीच दशकों पुराने मधुर संबंधों का पता चला है। आबे के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री नोबुसुके किशी द्वारा समर्थित कम्युनिस्ट-विरोधी आंदोलन के बीच 'यूनिफिकेशन चर्च' को 1968 में जापान में धार्मिक संगठन के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था।

'छोरी 2' प्राइम वीडियो पर 11 अप्रैल को रिलीज होगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नुसरत भरूचा अभिनीत 'छोरी 2' प्राइम वीडियो पर 11 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। प्राइम वीडियो ने मंगलवार को यह घोषणा की। यह फिल्म वर्ष 2021 में रिलीज़ हुई फिल्म 'छोरी' का सीक्वल है, जो वर्ष 2017 की मराठी हॉरर फिल्म 'लपाछपी' का रीमेक थी। इसकी कहानी एक गर्भवती महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके अजन्मे बच्चे को बुरी आत्माओं द्वारा निशाना बनाया जाता है।

'छोरी 2' का निर्देशन विशाल फुरिया ने किया है। फिल्म में सोहा अली खान, गश्मीर महाजनी, सौरभ गोयल, पल्लवी अजय, कुलदीप सरीन और हार्दिका शर्मा भी नजर आएंगे। फिल्म में 'साक्षी' का किरदार नुसरत भरूचा निभाएंगी। प्राइम वीडियो ने अपने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर फिल्म का टीजर साझा कर फिल्म के 11 अप्रैल को रिलीज होने की जानकारी दी।

कॉमेडी के नाम पर किसी को भी अपमानित करना गलत है : कंगना रनौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर पर हास्य कलाकार कुणाल कामरा की टिप्पणी से जुड़े विवाद को लेकर मंगलवार को कहा कि कॉमेडी के नाम पर किसी को भी अपमानित करना गलत है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद रनौत यहां संसद के बाहर पत्रकारों से बात कर रही थीं। उन्होंने कहा, आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान करना (अच्छा नहीं है)। आप कॉमेडी के नाम पर किसी का अपमान कर रहे हैं, उन्होंने जो भी किया है उसकी अनदेखी कर रहे हैं। शिंदे जी पहले कभी ऑटोरिक्शा चलाते थे।''

रनौत ने कहा, ''वह अपने दम पर आज यहां तक ड्ड्डपहुंचे हैं। उनकी (कामरा की) विश्वसनीयता क्या है? ये कौन लोग हैं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया? अगर वे लिख सकते हैं, तो मैं कहूंगी कि साहित्य लिखें या फिल्मों के लिए हास्य संवाद लिखें। कॉमेडी के नाम पर गाली देना, कॉमेडी के नाम पर हमारे धर्मग्रंथों का मजाक उड़ाना, लोगों, माताओं और बहनों का मजाक उड़ाना (सही नहीं है)।'' कामरा ने फिल्म ''दिल तो पागल है'' के एक गीत का संशोधित गीत (पैरोडी) गाया था, जिसमें शिंदे को जाहिर तौर पर ''गद्दार'' कहा गया था। उन्होंने महाराष्ट्र में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम, जिसमें शिवसेना और राकांपा में विभाजन भी शामिल है, पर चुटकुले बनाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को इस विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कामरा को अपनी ''घटिया कॉमेडी'' के लिए माफी मांगनी चाहिए। फडणवीस की टिप्पणी के समान विचार व्यक्त करते हुए रनौत ने कहा, ये लोग खुद को प्रभावशाली कहते हैं। इस दो मिनट की प्रसिद्धि के लिए समाज कहां जा रहा है? हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। जैसा कि फडणवीस जी ने कहा कि हमें जो कहना है, उसके लिए हमें कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जब आपसे कानूनी तौर पर पूछताछ की जाएगी तो क्या आप इस बात पर कामय रहेंगे? शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रविवार को मुंबई में खार क्षेत्र स्थित 'हैबिटेट कॉमेडी क्लब' में कथित रूप से तोड़फोड़ की थी, जहां कामरा का कार्यक्रम शूट किया गया था।

अगर मेरे पास दुनिया का सारा पैसा होता तो मैं पायलट बनना पसंद करता : ग्लेन फिलिप्स

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और मुश्किल कैच लपकने के कारण विश्व क्रिकेट में अपनी खास पहचान बनाने वाले न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स का कहना है कि अगर उनके पास दुनिया का सारा पैसा होता तो वह क्रिकेटर के बजाय पायलट बनना पसंद करते। फिलिप्स को उड़ान भरना जुनून की हद तक पसंद है और जब उन्हें इसके बारे में पूछा गया तो आईपीएल में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे इस ऑलराउंडर ने पीटीआई से कहा, यह मेरा बहुत बड़ा जुनून है। अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होता और मेरे पास दुनिया का सारा पैसा होता, तो ईमानदारी से कहूं तो शायद मैं एक पायलट बन गया होता। मुझे हवा में तैरना पसंद है।

दक्षिण अफ्रीका में जन्मा यह 28 वर्षीय क्रिकेटर न्यूजीलैंड की तरफ से तीनों प्रारूप में खेलता है। वह दो सीट वाला सेसना 152 विमान उड़ा चुके हैं लेकिन क्रिकेट में व्यस्त होने के कारण वह अपने इस शौक को पूरा नहीं कर पाते हैं। फिलिप्स को विश्व क्रिकेट में सबसे चपल क्षेत्ररक्षक माना जाता है। हाल में समाप्त हुई चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने हवा में लहराते हुए मुश्किल कैच लेने की अपनी अद्भुत क्षमता का शानदार परिचय दिया था। उन्होंने इसी तरह से विराट कोहली का कैच लेकर भारतीय बल्लेबाज को हतप्रभ कर दिया था। फिलिप्स ने इस बारे में कहा, मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से एक बड़ा हिस्सा है जो गति और चपलता के नजरिए से आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। इसलिए, मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि यह थोड़ा हद तक मेरी नैसर्गिक प्रतिभा से जुड़ा है लेकिन आखिर में आप अपने कौशल और प्रतिभा के दम पर ही आगे बढ़ते हैं।'' उन्होंने कहा, इसका दूसरा पहलू मेरी कड़ी मेहनत और अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। इसलिए अगर मैं कैच छोड़ता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया।

RNI No. 58061/93. Regn No.:
RNP/KA/BGS/2050/2018-2020
Posted at Bengaluru PSO
Mysore Road Bengaluru-560 026.

जीवन जीने के लिए गीता एक महान मंत्र है। व्यक्ति को अपने बाहर नहीं अपितु अपने अंतरमन में जीना चाहिए और बदलाव भी अंदर ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्संग ही प्रभु प्राप्ति का सबसे आसान तरीका व सर्वोत्तम मार्ग है इसलिए सत्संग जरूर करना चाहिए, सत्संग से तत्काल आनंद, शाश्वत सुख व शांति की प्राप्ति होती है।

बिजनेस गुरु विवेक बिंद्रा ने व्यापार में सफलता के गुर सिखाए

जीतो के दोनों चैप्टर ने किया आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जीतो) नॉर्थ और साउथ चैप्टर्स द्वारा 'सीखना बंद तो जीतना बंद' 10एक्स ग्रोथ विद वर्क एंड लाइफ बैलेंस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। साउथ चैप्टर के चेयरमैन रणजीत सोलंकी व नार्थ चैप्टर के चेयरमैन विमल कटारिया ने सभी का स्वागत किया।

इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बिजनेस गुरु एवं कोच डॉ. विवेक बिंद्रा ने ऑडियो-वीडियो के माध्यम से उद्यमियों को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि सही रणनीति, सकारात्मक सोच और निरंतर सीखने की आदत व्यापार को नई ऊँचाइयों तक ले जाती है। उन्होंने व्यापार में सफलता के लिए व्यक्तित्व की स्वच्छता, विचारों में तालमेल, असंभव को संभव करने की आदत, सकारात्मक मानसिकता, यादगार ब्रांडिंग और ग्राहकों की परवाह पर जोर दिया। कार्यक्रम में राजेश मेहता ने जैन व्यापारियों को उद्यमिता की ओर बढ़ने का संदेश दिया। प्रायोजक वैष्णोदेवी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रतिनिधियों व डॉ विवेक बिंद्रा का सम्मान किया गया। महामंत्री नितिन लुनिया एवं विजय सिंघवी ने संचालन किया। मुख्य प्रशिक्षक का परिचय कोमल भंडारी ने दिया। इस मौके पर अनेक राष्ट्रीय व स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

यशस्विनी स्वास्थ्य कार्ड — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के गोड़वाड़ भवन में जैन अल्पसंख्यक कल्याण एसोसिएशन के कार्यालय में रेणु रांका ने कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई जा रही 'यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा' के लिए 200 रजिस्ट्रेशन पूरे कर लिए। इस योजना के तहत कर्नाटक के निवासी कार्ड धारक चिह्नित अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकते हैं।

मुनिश्री पुलकितकुमार ने युवाओं को आत्मसंयम, नैतिकता और समर्पण का महत्व समझाया

सर्वोच्च पर्वत शिखर मुल्यानगिरि का किया आरोहण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चिकमगलूर। बेंगलूरु के तेरापंथ युवक परिषद् के सदस्यों ने 'फिट युवा, हिट युवा' अभियान के अंतर्गत कर्नाटक के सर्वोच्च शिखर मुल्यानगिरि पर्वत का आरोहण डॉ मुनि पुलकितकुमारजी के सान्निध्य में किया। इस मौके पर तेरापंथ धर्मसंघ के अनुयायियों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉ. मुनि पुलकितकुमारजी ने युवाओं को जीवन में अनुशासन, समर्पण और आध्यात्मिकता के महत्व को समझाते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके बाद परिषद के तत्वावधान में 'युवा कार्यशाला' का आयोजन किया जिसमें मुनिश्री ने युवाओं को आध्यात्मिकता एवं अनुशासन का नया दृष्टिकोण प्रदान किया। पुलकितकुमारजी ने प्रवचन के माध्यम से युवाओं को जीवन में आत्मसंयम, नैतिकता और समर्पण का महत्व समझाया। उनके प्रेरणादायक शब्दों ने उपस्थित सभी युवाओं को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में युवाओं को न केवल धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, बल्कि आत्म-विकास और नेतृत्व कौशल को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला। इस कार्यशाला के आयोजन में बेंगलूरु व चिकमगलूर की विभिन्न तेरांपथ संघ की संस्थाओं का सहयोग रहा। कार्यक्रम के बेंगलूरु तेयुप के अध्यक्ष विमल धारीवाल, तेरापंथ सभा के अध्यक्ष पारसमल भंसाली, मंत्री विनोद छाजेड़, संयोजक आलोक कुंडलियाँ आदि उपस्थित थे।

मित्रता को नाश करने वाली होती है माया : साध्वीश्री संयमलता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के राजाजीनगर स्थित तेरापंथ भवन में साध्वीश्री संयमलताजी के सान्निध्य में माया बनाम माया' कार्यशाला का आयोजन किया गया। साध्वीश्री ने माया सम्पन्न श्रावकों को संबोधित करते हुए कहा कि माया मित्रता को नाश करने वाली होती है। माया की चमक मानव को भ्रमित करने वाली है। समाज में होड़ा-होड़ी चल रही है। व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाकर प्रसन्न होते हैं। सब आडंबर में उलझे हुए हैं। आज व्यक्ति अपनी हर श्वांस पैसे में लगा रहा है, पर एक पैसा भी उस श्वांस में नहीं लगता है, अतः व्यक्ति पैसे तो कमाए पर माया से अशुभ कर्मों का बंधन करने से बचे।

एक छोटी सी माया हमारे अनेक भवों को बिगाड़ देती है। साध्वीश्री ने अनेक घटनाओं के माध्यम से माया के दुष्परिणाम बताते हुए माया में उलझने से बचने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा दी। साध्वीवृंद ने गीतिका के माध्यम से माया की व्याख्या की। साध्वी रौनकप्रभाजी ने दोनों माया के अर्थ बताते हुए प्रभु मल्लिनाथ के जीवन में हुई माया के परिणाम की जानकारी दी। इस अवसर पर तेरापंथ सभा राजाजीनगर के अध्यक्ष अशोक चौधरी, तेयुप के अध्यक्ष कमलेश चौकड़ियाँ, महिला मंडल की अध्यक्ष उषा चौधरी सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

अहिंसा में ही सबकी सुख-शांति और उन्नति का संदेश है : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के वीवी पुरम स्थित सिमंधर शांतिसूरी जैन श्वेतांबर संघ के तत्वावधान में मंगलवार को उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए जैनाचार्य विमलसागरसूरीजी ने कहा कि जो मानसिक हिंसा से बचने का प्रयत्न करता है, वही सच्चे अर्थ में साधक है। हिंसा दुःख, अभाव, बीमारी, गरीबी और रुकावटें लाती है। हिंसा द्रव्यात्मक हों या भावनात्मक, दोनों खतरनाक हैं। विचारों की हिंसा ही जीवन व्यवहार में उतरती है। बाहर जो हिंसा दिखाई देती है, उसका कोई न कोई अंश मनुष्य के भीतर जरूर होता है। हिंसा के परिणाम कभी सुखद नहीं होते। अहिंसा ही जीने का रास्ता है, हिंसा जीने का रास्ता नहीं है। अहिंसा की शुरुआत सबसे पहले अपने भोजन से करनी चाहिए। अन्न के साथ मन का सीधा संबंध है।

जैसा अन्न होता है, वैसा ही मनुष्य का मन बनता है। शुद्ध आहार हमारे विचारों को भी शुद्ध रखता है। आहारचर्या के बाद आसपास का वातावरण, शिक्षा, संस्कार, दृश्य-श्राव्य माध्यम, मित्र-परिजन और धनोपार्जन आदि अहिंसक जीवनशैली को जीवंत रखने के लिए आवश्यक पूरक तत्व हैं। इन सबके प्रयोगात्मक रूप प्रतिदिन की जीवनचर्या में देखे जा सकते हैं। अहिंसा पूर्णरूपेण मनोवैज्ञानिक तत्व है। इसमें सबकी सुख-शांति और उन्नति का संदेश है। मित्रता, प्रेम, भाईचारा, सहयोग, सौहार्द और समन्वय, सबकी भूमिका अहिंसा पर ही टिकी है।

आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि अहिंसा शुद्ध व सात्विक भावों की गंगोत्री है। अहिंसा से निष्पन्न विचार कभी किसी का अहित नहीं करते, बल्कि सबके हित का चिंतन करते हैं। सबके प्रति न्याय और सभी को समान धरातल पर देखने का दृष्टिकोण भी सिर्फ अहिंसा से ही संभव है, इसलिए अधिक से अधिक द्रव्यात्मक और भावनात्मक अहिंसा का परिपालन करना चाहिए। अहिंसक मनुष्य किसी का भी शत्रु नहीं होता, वह प्राणीमात्र तो मित्रवत देखता है। अहिंसा किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ती, उसमें निर्भय का वरदान है। विश्वशांति केवल अहिंसा के रास्ते से ही संभव है। हिंसा का मार्ग तो समग्र पृथ्वी को नष्ट कर देगा। इससे पूर्व विजयनगर से पदयात्रा करते हुए आचार्य विमलसागर सूरीश्वरजी, गणि पद्मविमलसागरजी और सहवर्ती श्रमणजन वीवी पुरम पहुंचे, जहां उनकर भावपूर्ण स्वागत हुआ ।

रामकृष्ण कॉलेज के छात्रों ने 30 मिनट में 300 तरह की चाय बनाकर बनाया कीर्तिमान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयम्बटूर/कुन्नूर। यहां टी बोर्ड इंडिया कुन्नूर और श्री रामकृष्ण कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोयंबटूर के खानपान एवं होटल प्रबंधन विभाग ने संयुक्त रूप से 24 मार्च को कॉलेज परिसर में 'टी क्राफ्टिंग-2025'का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आठ कॉलेजों के छात्रों ने आम लोगों के साथ मिलकर छह टीमें बनाईं और मात्र 30 मिनट के भीतर सफलतापूर्वक 300 तरह की चाय तैयार की। छात्रों ने मसालेदार चाय, हर्बल चाय, हल्दी चाय, आंवले की चाय, तुलसी चाय, पुदीने की चाय, मसाला चाय और शहद वाली चाय सहित कई तरह की चाय बनाकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उनके उल्लेखनीय प्रयास ने उन्हें 'कलाम की विश्व रिकॉर्ड बुक' में स्थान दिलाया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया।

रिकॉर्ड उत्सव समारोह की अध्यक्षता एस एन आर संस चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी आर. सुंदर ने की। श्री रामकृष्ण कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य एवं सचिव डॉ. बीएल शिवकुमार ने सभी का स्वागत किया। टी बोर्ड इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉ. एम. मुथुकुमार, आई.ए.एस. ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और सभा को संबोधित करते हुए कहा, चाय एक स्वस्थ पेय है, और इसके प्राकृतिक यौगिकों में औषधीय गुण होते हैं। कोविड-19 अवधि के दौरान किए गए शोध से पता चला है कि हल्दी और चाय ने भारतीय स्वास्थ्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे मृत्यु दर कम हुई है। इस विषय पर कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। मदुरै, त्रिची और नमक्कल में चाय के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इन प्रयासों को जारी रखते हुए, चाय बोर्ड ने कोयंबटूर में एक भव्य चाय महोत्सव आयोजित करने की योजना बनाई है। चाय की खेती कई क्षेत्रों में की जाती है, और जनता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बिना मिलावट के शुद्ध चाय पाउडर खरीदें। इससे चाय उद्योग से जुड़े लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा। इस कार्यक्रम में टी बोर्ड इंडिया, कुन्नूर के उपाध्यक्ष पी. राजेश चंदर और बोर्ड सदस्य के.के. मनोजकुमार ने उद्घाटन भाषण दिया। इसके बाद कलाम की विश्व रिकॉर्ड बुक में दर्ज किए गए कीर्तिमान को मान्यता देने वाले प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का समापन कैटरिंग एवं होटल प्रबंधन विभाग के प्रमुख आर. राजन के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

नि:शुल्क शिविर — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के स्वयंसेवकों ने मंगलवार को नेलमंगला स्थित सरकारी कॉलेज में एक नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जिसमें लगभग 300 विद्यार्थियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। विद्यार्थियों को कुपोषण और उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर विशेष ध्यान देने का परामर्श दिया गया। शिविर में नि:शुल्क दवाइयाँ वितरित की गईं।

जीवन के कल्याण के लिए की जाती है तपस्या : विनयमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

> अति मात्रा और अहितकारी आहार कभी नहीं करना चाहिए, अन्न का संयम अवश्य ही करना चाहिए।

बेंगलूरु। शहर के हीराबाग स्थानक में विराजित विनयमुनिजी खींचन ने अपने प्रवचन में कहा कि भगवान महावीर ने हमें आहार का महत्त्व बताया है। भूख लगने पर आहार करना चाहिए। अति मात्रा और अहितकारी आहार कभी नहीं करना चाहिए, अन्न का संयम अवश्य ही करना चाहिए। संतश्री ने कहा कि मौन तप भी एक महान् तप है। जीवन के कल्याण के लिए तपस्या की जाती है। तप व्यक्ति के जीवन में मानसिक बल के साथ आध्यात्मिक बल को बढ़ाता है। मुनिश्री ने कहा कि व्यक्ति को अपनी भूलों को स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए।

संस्कृति ने डिस्को किंग बप्पी लाहिरी को किया याद

चेन्नई। यहां संस्कृति कल्चरल फाउंडेशन के कलाकारों ने टी नगर स्थित वाणी महल में सुपार्श्व गायक बप्पी लाहिरी की याद में उन्ही के गीतों की प्रस्तुति का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि बप्पी लाहिड़ी, जिन्हें बप्पी दा के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय गायक, संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता थे, जो भारतीय सिनेमा में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते थे।

सभी का स्वागत संस्कृति के अध्यक्ष विमल चोरड़िया ने किया। पूर्व अध्यक्ष सुधीर कांकरिया ने संगीत जगत में बप्पी लाहिरी के योगदान और उनकी विशेष शैली डिस्को से अवगत कराया। कार्यक्रम की शुरुआत रीता चोरडिया, सरिता सुराणा रजनी गोयल एवं कार्यक्रम की संयोजिका एकता चोरारिया ने दीप प्रज्ज्वलित से की। संस्कृति के गायक कलाकार मंज़ू सारडा, अनामिका अग्रवाल, निर्मला कोठारी, महेश दम्मानी, राकेश बिनायकिया, अशोक कोठारी, रजनी गोयल, एकता चोरारिया, अरविंद इन्दौरिया, आनंद बिहानी, सुरेश चौरारिया, संगीता गादिया, चिराग जैन एवं विमल चोरड़िया ने बप्पी लाहिरी के गीतों की प्रस्तुति दी जिसे सभी दर्शकों ने खूब सराहा। संस्कृति कलाकार संदीप चौरारिया और बाल कलाकार विनीत लूणावत ने बप्पी दा की मिमिक्री की और दर्शकों को खूब हँसाया। संस्कृति कल्चरल फाउंडेशन के सभी दानदाताओं का सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। जयंतीलाल तेलीसरा ने संचालन किया।

Printed & Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com